● वर्ष-2
● अंक-180
रायपुर, मंगलवार
21 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

गरीबों के राशन पर अमीरों की नजर

भारत जब स्वतंत्र हुआ तब अंग्रेजों ने इस देश का इतना अधिक शोषण किया था कि देश की 70 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती थी। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और अकाल पड़ने के कारण बड़ी संख्या में भूख से लोगों की मौत हो जाया करती थी। स्वतंत्रता के बाद देश ने प्रगति की। खेती, किसानी में प्रगति हुई। देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मिलने लगा। तब से लेकर आज तक राशन दुकानों से अनाज की चोरी कोई नई बात नहीं है। वैसे भी गरीबी दूर करने के लिए जितनी योजनाएं बनती है, उससे गरीबों का कितना भला होता है यह कहना मुश्किल है लेकिन व्यापारियों, उद्योगपतियों, नेताओं और अधिकारियों की जेब में मोटी रकम चली जाती है। छत्तीसगढ़ में 2007 में डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 3 रु. किलो की दर से गरीब परिवार को 35 किलो चावल देने की योजना शुरु की थी। जैसे-जैसे गरीबों को ज्यादा फायदा होने लगता है, वैसे-वैसे ऐसी योजनाओं में धांधली की संभावना बढ़ती जाती है। गरीबों को मिलने अनाज में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए डॉ. रमन सरकार ने अनेक प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों को राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि भी मिली थी। 2018 के अंत में जब सरकार बदली तो नई सरकार ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ संशोधन किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के अलावा गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों को भी सस्ता अनाज देने की योजना शुरु हुई। कोरोना के समय पीडीएस के जरिए गरीबों को मिलने वाले अनाज में केंद्र सरकार के ओर से भी गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल दिए जाने लगा। यही से प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था में गड़बड़ियां शुरु हुई। विधानसभा में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपए के चावल की अफरा-तफरी की है। ऐसा ही आरोप डॉ. रमन सिंह ने भी प्रश्नकाल के दौरान लगाया था। दरअसल मामला राशन दुकानों में शेष बचे चावल, शक्कर, चना, नमक और गुड़ के स्टाक और खाद्य विभाग के पोर्टल में दिखाए जाने वाले स्टाक के अंतर से बवाल खड़ा हुआ है। वैसे तो पीडीएस आदेश नियंत्रक 2016 के तहत एक व्यवस्था बनी है कि शेष बचे अनाज को राशन दुकानदार अगले माह के आबंटन में एडजस्ट करेगा। लेकिन 2022 से ही मामला खुलकर सामने आया। ऐसा लगता है कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों ने राशन दुकानों से राशन नहीं लिया। जबकि खाद्य विभाग राशन कार्ड के हिसाब से आबंटन करता रहा, जो राशन बटा संभवतः उसे खुले बाजार बेच दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि खाद्य विभाग ने सितंबर 2022 में स्टाक की जांच की थी, जिसमें प्रदेश की कुल राशन दुकानें 13391 में से केवल 18 को छोड़ दें तो शेष के पास 96 हजार मीट्रिक टन चावल बचा हुआ था, जबकि विभाग के पास इस स्टाक की मात्रा 1 लाख 65 हजार मीट्रिक टन से अधिक की थी। इस हिसाब से लगभग 69 हजार मीट्रिक टन चावल का अंतर मिला। अब इस बात को लेकर विपक्ष सरकार पर 1 हजार करोड़ रुपए के चावल के घोटाले का आरोप लगा रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी पूर्व की रमन सरकार पर नान घोटाले के आरोप लगाती रही। नान घोटाले को लेकर भूपेश सरकार ने एसआईटी भी बनाई है, लेकिन चार साल हो गए अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। उल्टे जिन दो बड़े अधिकारियों पर नान घोटाले के आरोप लगे थे। और कार्यवाही हुई थी, वे अभी भूपेश सरकार में ताकतवर अधिकारी बने हुए है। इधर ईडी नान घोटाले के दोषी अधिकारियों को बचाने का आरोप भूपेश सरकार पर मढ़ रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने नान घोटाले की सुनवाई छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य राज्य में कराने का आग्रह किया है। कुल मिलाकर अनाज के घोटाले की एक फाईल बंद हुई नहीं है कि दूसरी फाइल खुल गई है। अब चुनाव तक कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर इस मामले को लेकर आरोप लगाते रहेंगे।

अमृतपाल पर चौतरफा कार्रवाई

नई दिल्ली। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर एक्शन जारी है। पुलिस की कई टीमें इसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहीं हैं। सोमवार को उसके समर्थकों पर एनएसए लगाया गया। वहीं, रविवार को उसके 34 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक उसके 112 समर्थक दबोचे जा चुके हैं। कई नजरबंद कर दिए गए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे पंजाब में सुरक्षाबल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के सांसद सिमरनजीत सिंह मान समेत 75 यूजर्स के ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिए गए। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के मामले में शनिवार को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में अभियान शुरू किया। पहले खबर आई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि अमृतपाल समेत कई अब भी फरार हैं। शनिवार दोपहर करीब एक बजे जैसे ही अमृतपाल का काफिला जालंधर के महितपुर गांव पहुंचा, पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर दी। इस बीच अमृतपाल गाड़ी में बैठकर भाग निकला।

सोमवार को पंजाब पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास करने के आरोप में हुई है। उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, 34 को दूसरे दिन और दो अन्य को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 10 हथियार भी बरामद किए गए हैं।

चार लोगों को हिरासत में लेने के बाद असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। इसमें अमृतपाल सिंह का चाचा हरजीत सिंह भी शामिल है। डिब्रूगढ़ भेजे जा रहे आरोपियों के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है। आईजीपी पंजाब, सुखचैन सिंह गिल के मुताबिक, वारिस पंजाब दे के इन लोगों के खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने कहा है कि वह अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उधर, अजनाला थाने पर हमले के आरोपी एवं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर रविवार को तीन और एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। जालंधर के सलेमा गांव में मिली उसकी काले रंग की ईसुजू गाड़ी में अवैध हथियार मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी और उसके गनरों को गिरफ्तार कर लिया है।

माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर पंजाब में सोमवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। अब इस प्रतिबंध को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जनता के हित में पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 21 मार्च दोपहर 12 बजे तक निलंबित की गई हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिए किया गया है।

संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान समेत 75 यूजर्स के ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिए हैं। सिमरनजीत मान ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की थी। पिछले दो दिनों में पंजाब के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वहीं, अमृतपाल को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए वारिस पंजाब दे के सदस्य हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रविवार को दाखिल याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता इमरान सिंह का आरोप है केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर जालंधर से अमृतपाल को अवैध हिरासत में रखा गया है, जिसका अभी तक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

अमृतसर, फाजिल्का, मोगा और मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ ही भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से लगती पंजाब की सीमा को सील कर दिया गया है। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में तनाव की स्थिति है। बीते 36 घंटों से पूरे गांव पर कड़ा पहरा है। बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं। जल्लूपुर खेड़ा के रास्तों पर जगह-जगह नाके लगा दिए गए हैं।

मानव बम तैयार कर रहा था अमृतपाल

पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व में जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें भी आयोजित की गई है और राज्य में फिलहाल पूरी तरह से शांति और सद्भाव है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में वारिस पंजाब डी के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर खोज शुरू होने के बाद से फरार है। अब खबर है कि अमृतपाल सिंह ने मानव बम की भर्ती के लिए पुनर्वास केंद्रों का इस्तेमाल किया था। खुफिया एजेंसियों के एक डोजियर ने सुझाव दिया कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह हथियार जमा करने और आत्मघाती हमले करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए नशामुक्ति केंद्रों और एक गुरुद्वारे का उपयोग कर रहे थे। डोजियर में दावा किया गया है कि सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई और विदेशों में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर पिछले साल दुबई से लौटे थे।

लंदन की घटना पर सिख समुदाय में नाराजगी

रविवार को लंदन में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की कोशिश की। इसको लेकर भारत के सिखों में जबरजस्त नाराजगी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे गिराने की घटना को लेकर सिख समुदाय ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। सभी के हाथों में भारतीय तिरंगा भी था। चाणक्यपुरी में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सैकड़ों सिख समुदाय के कई लोग जमा हुए और विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान वे नारेबाजी करते भी नजर आएं। उनके हाथों में तख्तियां भी थीं जिसपर लिखा था भारत हमारा स्वाभिमान है। सिख समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लंदन में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग से तिरंगा को उतारने की कोशिश की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का यह प्रयास नाकाम रहा और भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। खालिस्तानियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि हमने इस पर भारत की प्रतिक्रिया दे दी है। अपराधियों को गिरफ्तार करने की जरूरत है। हमने ब्रिटिश अधिकारियों को यूके उच्चायोग में सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।

पाकिस्तान भागने की फिराक में है अमृतपाल सिंह?

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के प्रमुखों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाकर गश्त तेज कर दी है। ऐसी संभावना है कि वारिस पंजाब डी प्रमुख अमृतपाल सिंह संभू सीमा पार कर सकता हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अमृतपाल की पगड़ी वाली और बिना पगड़ी वाली दो तस्वीरें के साथ बीएसएफ और एसएसबी की सभी इकाइयों को एक संदेश भेजा गया है। खालिस्तान समर्थक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। ऐसी संभावना है कि उसने पंजाब में भारत-नेपाल सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की हो। एक अधिकारी ने कहा, उन्हें सतर्क रहने और सीमा चौकियों पर तैनात सभी कर्मियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने शनिवार को जालंधर-मोगा रोड स्थित महतपुर में अमृतपाल को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। हालांकि, वह उनसे बच गया और सूत्रों ने कहा कि उसने अपना वाहन और मोबाइल फोन नकोदर के पास छोड़ दिया। राज्यव्यापी कार्रवाई में पुलिस ने शनिवार को उसके 78 साथियों को गिरफ्तार किया। अमृतपाल की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही और जिला पुलिस प्रमुखों ने पंजाब के प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च किया और राज्य सरकार ने सोमवार दोपहर तक इंटरनेट पर रोक लगा दी। पंजाब पुलिस ने रविवार को अमृतपाल और उसके सात साथियों के खिलाफ 12 बोर की छह राइफलें और 196 कारतूस बरामद करने का दावा करने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

प्रमुख समाचार

न तो ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और न मैं मुख्यमंत्री- तेजस्वी

पटना। 2024 को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष के अलग-अलग नेताओं का प्रधानमंत्री पद की रेस में नाम आ रहा है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं, तब से उनका भी नाम इस रेस में आ रहा था। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की भी कोशिश की थी। उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी किया था। हालांकि, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और न ही मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हम जहां हैं, वहीं खुश हैं। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर तेजस्वी का नाम चर्चा में रहता है। विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करके बहुत खुश है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करने वाले नेताओं को भ्रष्टाचार के नाम पर भाजपा निशाना बना रही है। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे बीच दूरी की कल्पना कर सकता है।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। यह राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश, असम में दर्ज तीन प्राथमिकियों को लखनऊ स्थानांतरित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पवन खेड़ा को पहले प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नियमित जमानत लेने के लिए लखनऊ की अदालत में पेश होना होगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने की है। पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी के छावनी थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं जबकि तीसरी प्राथमिकी असम में दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने पूर्व में भी खेड़ा को अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को 17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में असम पुलिस ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

ओआरओपी बकाये के भुगतान पर दिए फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है केंद्र- न्यायालय

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने पर उसके 2022 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है और उसने केंद्र से 2019-2022 के लिए उन्हें अगले साल 28 फरवरी तक 28,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई शुरू होने पर ओआरओपी के बकाये के भुगतान पर केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के लिए समय दिया। उसने कहा, ''केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में इस अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है।'' पीठ ने कहा कि 25 लाख पेंशनभोगियों में से चार लाख ओआरओपी योजना के योग्य नहीं पाए गए क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिल रही थी और केंद्र ने 30 अप्रैल 2023 तक बकाये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया था।

अविवेकपूर्ण, श्रद्धा और निक्की मर्डर केस के बाद दी गई थी याचिका-कोर्ट

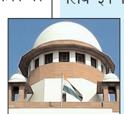

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में अनिवार्य पंजीकरण की मांग करके अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने की आड़ में लिव-इन रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि यह क्या है? लोग यहां कुछ भी लेकर आते हैं? हम ऐसे मामलों पर लागत लगाना शुरू करेंगे। किसके साथ पंजीकरण? केंद्र सरकार के साथ? लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से केंद्र सरकार को क्या लेना-देना? क्या आप इन लोगों की देखभाल, सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? याचिका एडवोकेट ममता रानी द्वारा दायर की गई थी और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, कृषि मंत्री से हुई मुलाकात

नयी दिल्ली। किसान आंदोलन को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में हजारों किसान जुट गए हैं। रामलीला मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान महापंचायत सरकार से वादों को पूरा करने की मांग कर रहा है। किसानों का अनुरोध है कि जो लिखित वादे उनसे किए गए थे, उनको पूरा किया जाए। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, तब किसानों का आंदोलन हुआ था। आंदोलन काफी लंबा चला था। बाद में कृषि कानूनों को वापस लिया गया। किसानों को आश्वासन देकर उनका आंदोलन खत्म कराया गया था। इन सब के बीच किसान संगठनों का दावा है कि जो उनसे वादे किए गए थे, उसे पूरा नहीं किया गया है। यही कारण है कि अब वह एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य दर्शन पाल ने कहा कि अगर एमएसपी कर्जमाफी और पेंशन को लेकर जो उनकी मांगें हैं उसे पूरा नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

संसद में हंगामा बेवजह, नियम-कानून से ऊपर कोई नहीं है

आशुतोष चतुर्वेदी

कई दिनों से संसद में हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा है। कभी कभार ऐसी भी खबरें आती रहीं हैं कि कुछ सांसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर चले गये या अनुपस्थित रहे। हाल में जापान की संसद ने सदन से अनुपस्थित रहने के कारण योशिकाजू हिगाशितानी नामक एक सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी। जापान के संसदीय इतिहास में पहली बार गैरहाजिर रहने वाले किसी सदस्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है। इसके पहले वहां खराब बर्ताव के कारण एक सांसद की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। योशिकाजू हिगाशितानी यूट्यूबर हैं और एक शो को भी होस्ट करते हैं। वे पूरा वक्त अपने यूट्यूब चैनल को देते थे और संसद सत्र से गायब रहते थे। खबरों के अनुसार, योशिकाजू की सदस्यता खत्म करने का फैसला इसलिए लिया गया, ताकि राजनीतिज्ञों को यह संदेश दिया जा सके कि अगर वे सांसद बनते हैं, तो उन्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। अपने देश में भी संविधान निर्माताओं ने ऐसी परिकल्पना की थी कि संसद और विधानसभा के माध्यम से कानून बनेंगे और उनके द्वारा जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जायेगा। सदन में विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के नेताओं का किसी मुद्दे पर नजरिया अलग हो सकता है। इसकी वजह से थोड़े समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही न चलना उचित नहीं है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी जितनी सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की भी है। दुर्भाग्य यह है कि यह मान लिया गया है कि किसी बात को रखने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका हंगामा करना है। हाल में एक अन्य खबर आयी कि ब्रिटेन

के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी लंदन के हाइड पार्क में अपने कुत्ते को बिना चेन के टहलाते हुए देखे गये। किसी ने उसकी वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि यह स्वीकार्य नहीं है। हाइड पार्क के नियमों के अनुसार पार्क में कुत्ता बिना चेन घुमाना जुर्म है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को खतरा हो सकता है। पुलिस ने बताया है कि वहां उस समय मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने प्रधानमंत्री सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से बात की और उन्हें नियमों के बारे में जानकारी दी। पश्चिमी देशों में सैकड़ों खामियां हैं। उनकी औपनिवेशिक नीतियों ने सैकड़ों देशों और समाज को तबाह कर दिया था। अनेक ऐसे विषय हैं, जिनको लेकर उनकी कटु आलोचना की जा सकती है, लेकिन नियम-कानून सबके लिए बराबर होता है, यह उनसे सीखा जा सकता है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आप भले ही कितने खास हों, आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसकी तुलना में भारत में किसी सांसद, मंत्री अथवा सेलिब्रिटी को हाथ लगा कर तो देखिए, किस तरह पूरे तंत्र पर हल्ला बोल दिया जाता है। अपने देश में नेता व अधिकारी और उनके परिजनों की दबंगई के मामले रोजाना सामने आते हैं। यह बात कोई छुपी हुई नहीं है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जब भी किसी पहुंच वाले शख्स को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आ जाते हैं। नेता-अभिनेता को तो छोड़िए, उनके सगे-संबंधी भी अपने आपको कानून से ऊपर मानते हैं। सैकड़ों में एक मामला सामने आता है, जब कोई अधिकारी उनसे नियम कानून का पालन करवाने की हिम्मत दिखाता है।

इसके पहले भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और तत्कालीन वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप में लंदन पुलिस ने जुर्माना लगाया था। दोनों नेताओं ने जुर्माना देने के साथ माफी भी मांगी थी। दरअसल, कोरोना काल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने आधिकारिक निवास में एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें ऋषि सुनक समेत चुनिंदा लोग शामिल हुए थे। उस दौरान ब्रिटेन में लॉक डाउन के नियम लागू थे और पार्टियों के आयोजन पर प्रतिबंध था। ऋषि सुनक कसूर यह था कि वे प्रधानमंत्री की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। मुझे याद है, जब मैं बीबीसी लंदन में कार्यरत था, उस दौरान टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनका 16 साल का बेटा इम्तिहान खत्म होने की खुशी में एक पब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इस दौरान उसे कुछ ज्यादा चढ़ गयी और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। बाद में टोनी ब्लेयर की पत्नी शैरी ब्लेयर को थाने जाकर बेटे को छुड़ाना पड़ा था। टोनी ब्लेयर या फिर किसी अन्य ने उसके बचाव की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर इस घटना पर खेद प्रकट किया गया था। इस सबका संदेश साफ है कि भले ही आप आम हों या खास, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं। इसकी तुलना में भारत में नियम और कानून की अनदेखी जैसे हमारी प्रवृत्ति बन गयी है।

भाजपा का बूथ सशक्तिकरण महा अभियान शुरू

मुंगेली। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बूथ सशक्तिकरण का महा अभियान प्रारंभ कर दिया है।

यह अभियान 17 से 27 मार्च तक चलेगा,जिसमें जिले के सभी 102 शक्ति केंद्रों में आज भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता पहुंचे तथा बूथों की बैठकें लेकर बूथ सशक्तिकरण के लिए पार्टी द्वारा जारी किए गए 24 तरह के कार्यों की जानकारी ली। बैठक में उपस्थित बूथ अध्यक्षों, प्रत्येक बूथ के 11 प्रमुख कार्यकर्ताओं, महिला एवं युवा प्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पार्टी द्वारा जारी किए गए कार्यों को 10 दिन के अंदर पूरा करने का संकल्प दिलाया गया।

जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने बताया कि सभी शक्ति केंद्रों में भाजपा विस्तारकों द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का वाचन किया गया एवं संगठनात्मक एवं रचनात्मक कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं, बूथ प्रभारियों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, महिला एवं युवा कार्यकर्ताओं से इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ताकत झोंकने का आह्वान किया गया।

जिला भाजपा मीडिया सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले की दो विधानसभाओं के 9 मंडलों में यह कार्य शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथ तक पहुंचा जा रहा है, इस कार्य में पार्टी के सभी प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय व मंडल स्तरीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। आज जिन नेताओं ने बूथ पर पहुंचकर अपनी सहभागिता दी, उनमें से प्रमुख रूप से

जिलाभाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक, जिला महामंत्री निश्चल गुप्ता, गुरमीत सलूजा,गिरीश शुक्ला,राजेंद्र वैष्णव, संजय वर्मा,सुनील पाठक,आशीष मिश्रा,राणाप्रताप सिंह,शंकर सिंह,सोम वैष्णव,नरेश पटेल,दिनेश साहू,महाजन जायसवाल, प्रदीप मिश्रा, हरिशंकर वर्मा,कैलाश सिंह ठाकुर,प्रदीप पाण्डेय, कोटूमल दादवानी आदि ने सभी शक्ति केंद्रों की बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया और विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया।

सरकार के खिलाफगुस्सा दिखा- राणाप्रताप सिंह

भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष राणाप्रताप सिंह ने कहा कि शक्ति केंद्रों में हुई बैठकों से यह साफ हो गया कि लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो चुका है, क्योंकि इन 4 वर्षों में सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए और सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है, इसलिए लोगों में आक्रोश है।

बघमारा शक्ति केंद्र में भाजपा का बूथ सशक्तिकरण बैठक व राष्ट्रपति के अभिभाषण का हुआ वाचन

बालोद। बालोद ग्रामीण मंडल के बघमरा शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक सम्पन्न हुई साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी वाचन बैठक में किया गया। ज्ञात हो कि भाजपा द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान 17 मार्च से 27 तक संपन्न होगा। बघमरा शक्ति केंद्र मे बैठक लेने हेतु विस्तारक के रूप में भाजपा नेता सुरेंद्र देशमुख उपस्थित रहे।

उक्त बैठक में सुरेंद्र देशमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णरूपेण लोकतांत्रिक पार्टी है जहां किसी व्यक्ति या परिवार की नही चलती बल्कि संगठन का निर्देश व मार्गदर्शन ही सर्वोपरि माना जाता है साथ ही साथ हमारे पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी क्रमबद्ध चलने पर बल देता है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है पर केवल और केवल अपने मजबूत बूथ के कारण है, ऐसे में हमे अपने बूथों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तब हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा और हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा तब हमारा मंडल मजबूत होगा ऐसे ही जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक व्यवस्था के कारण मजबूत हो पाती है। बूथ सशक्तिकरण अभियान संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है क्योंकि हमारा एक एक बूथ मजबूत होगा तभी हमारा विशाल संगठन मजबूत होगा। मण्डल व शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथों में प्रवास करना होगा, बैठकें लेनी होंगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना होगा तब कहीं हमारे यह अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी। आगे सुरेंद्र ने कहा कि संगठन की रीति नीति, कार्यपद्धति बूथ समिति की जानकारी हो। बैठक पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी वचन सुरेंद्र देशमुख के द्वारा किया गया, महामहिम के अभिभाषण में गरीब कल्याण को प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था में तेजी, विकसित भारत का विजन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। बैठक में प्रमुख रूप से शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

25 मार्च को गेवरा से आंदोलन की शुरुआत

■ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमडी को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। कोरबा जिलान्तर्गत एसईसीएल के भू-विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति ने सीएमडी कार्यालय पहुंचकर आंदोलन की चेतावनी दी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 चरण में आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। इसके तहत जिले की खदानों को बारी.बारी बंद कर आंदोलन किया जाएगा।

समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बिलासपुर मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च को एसईसीएल गेवरा क्षेत्र में सम्पूर्ण खदान बंद किया जाएगा। आगामी 5 अप्रैल को दीपका, 16 अप्रैल को कुसमुंडा, 25 अप्रैल को कोरबा क्षेत्र में सम्पूर्ण खदान बंद किया जाएगा। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो 5 मई को रेल और सड़क जाम किया जाएगा। उनका कहना है कि पूर्व में अनेक बार बैठकों में लिए गए निर्णय और आश्वासन, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया गया है। इसके कारण कोरबा जिले में एसईसीएल की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र के भू-विस्थापित परिवार अपने अधिकार को पाने के लिए भटक रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार के पुराने लंबित मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाना शामिल है। इसके अलावा उनका कहना है कि एक खाता एक

रोजगार नियम के विरुद्ध अलग-अलग खाता का संयोजन, रोजगार से वंचितों को रोजगार प्रदान किया जाए। एसईसीएल में लागू कोल इंडिया पॉलिसी 2012 को वापस लिया जाए। हर खाते में स्थायी रोजगार और नौकरी प्रदान की जाए।

वर्ष 2010 से इस पॉलिसी को अमल में लाने का फैसला लिया गया था। उसके पहले वर्ष 2004-2009 के अर्जन के मामलो में सभी मूल खातेदार एवं पैतृक बंटवारे से सहखातेदार को रोजगार दिया जाए। भू-विस्थापित परिवारों के शेष बेरोजगार युवाओं को खदान परिक्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की 100 फीसदी व्यवस्था किया जाए। बसाहट के लिए 15 डिसमिल भूमि, बसाहट की एवज में 25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाए। रलिया, भिलाईबाजार, हरदीबाजार सहित अन्य सभी ग्रामों में हुए आंशिक अधिग्रहण को रद्द किया जाए। गांव का सम्पूर्ण अर्जन किया जाना शामिल है। वर्तमान में दीपकाए कुसमुंडा गेवरा में लागू बसाहट के एवज में राशि, भू-विस्थापितो को टेंडर इत्यादि सुविधाओं को कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सराईपाली परियोजना में भी प्रदान किया जाए। गेवरा क्षेत्र अंतर्गत नई रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों की परिसम्पत्तियों का मुआवजा तत्काल भुगतान सहित अन्य मांग शामिल है।

फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को निगम ने हटाया

सामान फैलाकर अनाधिकृत रूप से व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

दुर्ग। नगर पालिक निगम फ्राट द बाइट अभियान का एक बड़ा हिसा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन व आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के नेतृत्व पर मोर शहर मोर जिम्मेदारी एवं फ्राट द बाईट मुहिम के अन्तर्गत दुर्ग नगर निगम में प्रतिदिन वार्ड वार अभियान चल रहा है इन गतिविधि पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिंसमे प्रतिदिन नालियों की तली की सफाई,सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, लगातार झाड़ियों की कटाई,बाजार क्षेत्रो में दुकानदारो द्वारा झिल्ली पन्नी बेचने पर टीम द्वारा कार्रवाही के साथ जुर्माना भी लिया जा रहा है और मुक्कड़ की सफाई मच्छर उन्मूलन कार्य एवं मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए विशेष फोकस, सड़को पर सी एंड डी मलबे की साफ सफाई किया जा रहा है। आज मिनी माता चौक पुलगांव के आस पास से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। रोका - छेका

शहर के मुख्य चौक चौराहों व गलियों

से आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठान में छोड़ा गया।शहर क्षेत्र के नहर नालाओ की सफाई के साथ साथ यातायात व्यवस्थित के अलावा चौक चौराहो के पोल से बैनर पोस्टर हटाने का कार्य किया गया। पुलगांव मिनी माता चौक से अमले ने सड़क फुटपाथ में सामान फैलाकर अनाधिकृत रूप से व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्थल से हटाकर सड़क, फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अवैध रूप से सड़क के किनारे व फुटपाथ पर कब्जा कर पान ठेले,फल ठेले,कपड़े दुकान के बाहर समान, कपड़े व अन्य सामग्रियों को

फैलाकर दुकानें लगाई जा रही थी। सड़क, फुटपाथ पर मुख्य मार्ग के किनारे दुकानें सजाने से अनावश्यक भीड़ एकत्रित होती थी, इससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी और आम नागरिकों एवम वाहन चालकों को आवागमन में असुविधा होती थी। शहर भ्रमण के दौरान आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने उक्त स्थल का निरीक्षण भी किया। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अधिकारी दुर्गेश गुप्ता,सहायक भवन निरीक्षण विनोद मांझी द्वारा सड़क व फुटपाथ में दुकान लगाने लोगों को समझाइश दी गई दिन निर्धारित कर पहुंच रहा दल- अभियान में वार्डो के घरों में अब तक स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम पहुंच रही है। निगम स्वास्थ्य विभाग कूलर आदि के साथ ही ऐसी जगहों पर जहां जलस्त्रोत होने की संभावना है नष्ट किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।कार्रवाही के दौरान भुवनदास साहू,शशिकांत यादव,ईश्वर वर्मा सहित टीम अमला मौजूद रहें।

कोरबा में तस्करों के हौसले बुलंद

जंगल में अवैध रूप से खोद रहे थे मिट्टी, 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। अब तस्कर अवैध रूप से मिट्टी खोदने के लिए जंगल के अंदर तक जा पहुंचे हैं। वन विभाग की टीम ने सोमवार को तस्करों से दो जेसीबी और तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। आरोपी निजी जमीन बताकर वहां मिट्टी उत्खनन का काम कर रहे थे। तभी इसकी सूचना वन विभाग को मिल गई। फिलहाल विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। मामला बालको वन परिक्षेत्र के ग्राम चुईया का है।

जंगल के भीतर वन भूमि में मिट्टी का अवैध रूप से उत्खनन करने के मामले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। ग्राम चुईया में अवैध रूप से चल रहे काम की शिकायत विभाग को मिली थी। वन परिक्षेत्राधिकारी जन्यत सरकार ने बताया, चुहिया निवासी पुहुक राम ने निजी जमीन पर खुदाई करने अनुमति ली थी। वहां खुदाई करते-करते जंगल के अंदर पहुंच गया। इसके बाद टीम ने जब्ती की कार्रवाई की है।

चुईया ईलाके में इससे पहले भी रेत का अवैध रुप से परिवहन करने की शिकायत वन विभाग को मिली थी, जिसके आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन परिक्षेत्राधिकारी ने कहा कि अवैध कार्यों के खिलाफ उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रेत और मिट्टी तस्कर काफी सक्रिय हैं। समय-समय पर वन विभाग और खनिज विभाग कार्यवाही करते हैं।

भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत शक्ति केन्द्रों की बैठक

कोरबा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बूथों पर कार्य योजना बना यह कार्यक्रम किया जा रहा हैं। प्रत्येक शक्तिकेन्द्रों के प्रत्येक बूथों में इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रभारी नियुक्त किये गए। मंडल पाली अंतर्गत 13 शक्तिकेन्द्रों के 69 बूथों तक पहुंचने विस्तारक व सहविस्तारक नियुक्त किये गए हैंए जिन्होंने अपने अपने प्रभार क्षेत्र पहुंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इसी कड़ी में पाली शक्तिकेन्द्र अंतर्गत प्रथम दिवस यह बैठक आयोजित की गयी, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का वाचन किया गया। प्रभारियों ने आगामी 10 दिन के अपने प्रवास की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी।

बैठक में जिले के संगठन सह प्रभारी गोपाल साहू, जिला मंत्री अजय जायसवाल, मंडल अध्यक्ष रोशन ठाकुर, महामंत्री विवेक कौशिक, विस्तारक संजू अजय जायसवाल, सहविस्तारक पुष्पा जायसवाल, शक्तिकेन्द्र प्रभारी कीर्ति कश्यपए संयोजक चंद्रशेखर पटेल, पूर्व पार्षद प्रयाग नरायण, पूर्व एल्डरमैन गीता शुक्ला, पार्षद राजेश पारवानी, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक विभूति कश्यप, हरीश चावड़ा, अनिल जायसवाल, भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी दीपक दीपक शर्मा, अनिल जायसवाल, दाऊ राम साहू, अनिल जायसवाल, घनश्याम पटेल, भाजयुमो महामंत्री विशाल मोटवानी, सहित समस्त बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता व आम नागरिक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

फसल मुआवजा प्रकरण को लेकर 21 को एसडीएम कार्यालय का घेराव : माकपा

कोरबा। कोरबा जिले में एसईसीएल के बलगी सुराकछार खदान के भू-धसान से प्रभावित किसानों को बीते 3 वर्ष का फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने बैठक करने के बाद माकपा प्रतिनिधिमंडल ने कटघोरा एसडीएम कार्यालय का 21 मार्च को घेराव का नोटिस कटघोरा एसडीएम सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये आक्रोशित किसानों की बैठक सुराकछार बस्ती में हुई। बैठक में गणेश राम, मोहर दास, महिपाल सिंह कंवर, पिला दादू, रामायण सिंह, सावित्री चौहान, दुज बाई, झुल बाई, सुमित्रा बाई, बेद कुंवर, सोन कुंवर, बूंद कुंवर, सुधीर, मीरा बाई के साथ बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित थे। किसानों ने बैठक में 21 मार्च को कटघोरा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की रूपरेखा भी बनाई गयी।

42 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत

कोरबा। पुरानी बस्ती में निवासरत एक 42 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो जाने की जानकारी मिली हैं। जिसे कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए कोरबा पुरानी बस्ती कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया हैं। जानकारी के अनुसार कोरबा पुरानी बस्ती निवासी एक 42 वर्षीय महिला जो बिलासपुर अपने ससुराल में रह रही थी। जिन्हें 15 मार्च को सर्दी-खांसी की शिकायत के बाद स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए, ले जाया गया। जहाँ कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। दूसरे दिन फिर तबियत बिगड़ने पर बिलासपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां जांच के बाद निमोनिया होने के साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उसे वेंटिलेटर में रखा गया साथ ही कोविड जांच की गई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महिला की मौत के बाद संपर्क में आने वालों ने किया खुद को आइसोलेटः-दो दिन के इलाज के बाद उक्त महिला की मौत हो गयी।

हजारों क्विंटल महुआ और देसी शराब बनाने का सामान जप्त

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान ग्राम चांदन में देर रात देशी शराब बनाने की फैक्ट्री को आबकारी विभाग ने सील किया। लगभग 3.50 लाख रुपए का महुआ शराब और शराब बनाने के अन्य सामान सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी सहायक आयुक्त विकास गोस्वामी के दिशानिर्देश पर आबकारी टीम ने ग्राम चांदन में आरोपी लाभो राम साहू, पिता शंकर साहू के यहां छापामार कार्रवाई की। इस दौरान लाभो राम के यहां से बड़ी मात्रा में 3400 किलो महुआ लाहन, शराब बनाने के बर्तन, गैस सिलेंडर चुल्हा और बनी हुई महुआ शराब जप्त की गई। जप्त शराब महुआ लाहन सहित अन्य सामान की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपए है। इस मामले में आरोपी लाभो राम को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।

हाट-बाजार में पसरा शुल्क नहीं लेने के निर्देश

कांकेर। जिले के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार (पटेल) समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन सुमीत अग्रवाल द्वारा जिले के ग्रामीण हाट-बाजारों में टोकरी या सिरभार से विक्रय के लिए लाने वाले साग-सब्जी सहित अन्य सामग्रियों पर विक्रेता से पसरा शुल्क नहीं लेने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क लेने की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिले के ग्राम करप में रविवार को आयोजित कोसरिया मरार पटेल समाज के महासम्मेलन में दी गई थी, जिस पर उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों में इसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कोबरा ने परिवार को बनाया बंधक, घंटों बैठा रहा

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रविवार रात झमझम बारिश एक परिवार के लिए मुसीबत बनकर आई। घर में घुसे एक कोबरा सांप ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। चौखट पर फन फैलाए कोबरा को देख परिवार की सांसें अटक गईं। सभी सदस्य घर के कमरे में बनी अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठ गए। घंटों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। इस बीच पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। उन्होंने कोबरा को पकड़ा। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। हालांकि पूरा परिवार उसी समय घर छोड़कर भी चला गया। दरअसल, पूरा मामला दादर खुर्द का है। यहां एक कमरे में पति और बेटे के साथ किराये से रहने वाली महिला सरस्वती यादव रविवार रात खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक कोबरा अंदर घुस आया। महिला की नजर उस पर पड़ी तो डर से चीख पड़ी। इसके बाद पूरा परिवार भाग कर कमरे के कोने में बनी अलमारी पर चढ़ गया। इस दौरान कोबरा कमरे की चौखट के पास ही फन फैलाए बैठा रहा।

ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन को ग्रामीणों, समूह की महिलाओं ने सुना

प्रधानमंत्री मोदी ने नईदिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ऑनलाइन किया उद्घाटन

जांजगीर चांपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का उद्घाटन किया। ग्लोबल मिलेट्स के ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिले के कृषकों, ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों की महिलाओं, अधिकारी कर्मचारियों ने सुना।

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ ज्योति पटेल ने बताया कि जिला, जनपद से लेकर ग्राम पंचायत तक ऑनलाइन प्रसारण की व्यवस्था की गई।

प्रधानमंत्री जी के दिए गए उदबोधन को ऑनलाइन माध्यम सुना और आत्मसात करने का संकल्प लिया। जनपद पंचायत नवागढ़ में सेमरा कलस्टर में ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह, ग्रामीणों ने सुना। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के कार्यक्रम में जनपद पंचायत डभरा के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर एस नायक, जनप्रतिनिधि श्रीमती हेमबाई कर्ष, श्रीमती सविता बाई, श्रीमती पिंकी बाई, रंभा बाई सहित विभिन्न विभागो के कर्मचारी-अधिकारी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कैडर्स, वेबिनार के द्वारा जुड़कर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के कार्यक्रम में जनपद पंचायत सक्ती के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कर्मचारी- अधिकारी एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कैडर्स वेबिनार के द्वारा जुड़कर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उदबोधन के माध्यम से जानकारी प्राप्त किये। इसी तरह जनपद पंचायत पामगढ़, बलौदा में ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन को सुना गया। सक्ति और जांजगीर जिले के सभी जनपद पंचायत में प्रतिभागियों को कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई थी, जिसमे जिला कृषि विभाग के एफ्पीओ किसान और क्लस्टर स्तरीय स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग लिए।

नक्सलियों ने आलपरस सड़क निर्माण में लगे 9 वाहनों को किया आग के हवाले

कांकेर। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलपरस के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य में लगे 9 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बिना सूचना दिए सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, इस बीच नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम देते हुए वहां मौजूद 8 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया है। बता दें कि हाल ही में घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर चिलपरस में बीएसएफ कैंप स्थापित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम आलपरस के

पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य में 8 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन लगी हुई थी। बीती रात में नक्सलियों ने वहां मौजूद मजदूरों को बंधक बनाकर एक-एक कर गाड़ियों में आग लगाने के बाद ग्रामीण मजदूरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गये। आज सोमवार सुबह नक्सली वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। कांकेर एसपी शलभ कुमार का कहना है कि ग्राम आलपरस में क्या कार्य चल रहा है, इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। पुलिस नक्सली आगजनी के वारदात की जांच कर रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जापानी पीएम ने मोदी को जी-7 बैठक के लिए किया आमंत्रित

नई दिल्ली। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में जी-7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले सोमवार सुबह जापानी प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली जी7 की बैठकों की प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत हुई।

राहुल गांधी को माफी मांगनी ही चाहिए : हरदीप पुरी

नईदिल्ली। राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। देश में इस बयान को लेकर कांग्रेस की भद्द तो पिट ही रही है। बीजेपी भी राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर अड़ी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर जाता है तो उसे बोलने की आजादी है लेकिन इसके साथ ही वह आजादी भी आती है जिसे उत्तरदायित्व की आवश्यकता कहा जाता है। पुरी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं लेकिन मिस्टर गांधी ब्रिटेन गए और कहा कि भारतीय लोकतंत्र बुनियादी ढांचे पर हमले का सामना कर रहा है।

संजय राउत की बढ़ी मुश्किल फिर नया केस दर्ज

मुंबई। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। राउत के खिलाफ नया मामला सोलापुर जिले के बरशी थाने में मामला दर्ज किया गया। एक मामले में संजय राउत ने पीड़ित लड़की की फोटो ट्वीट की थी। इसी के चलते जानकारी सामने आ रही है कि पीड़ित लड़की की पहचान सामने आने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होने से राउत की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। बरसी में कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस घटना में पीड़िता की फोटो संजय राउत ने ट्वीट की थी। पीड़िता नाबालिग थी और इस तस्वीर से उसकी पहचान होने पर संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि संजय राउत के खिलाफ किस धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के खिलाफ धारा 23 पॉक्सो, 74 जुवेनाइल जस्टिस, आईपीसी 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बीआरएस नेता कविता पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुईं

नयी दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरे चरण की पूछताछ के लिए सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद की सदस्य कविता (44) से इस मामले में सबसे पहले 11 मार्च को पूछताछ की गयी थी जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को फिर से तलब किया गया था लेकिन वह मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत दिए जाने की अपनी लंबित याचिका का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई थीं। संघीय जांच एजेंसी ने उनके दावों के खारिज कर दिया था और उन्हें 20 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। ऐसी जानकारी है कि 11 मार्च को ईडी के कार्यालय में करीब नौ घंटे तक पूछताछ के दौरान कविता से हैदराबाद स्थित कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों को लेकर सवाल-जवाब किए गए। कविता के कथित करीबी समझे जाने वाले पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सिसोदिया की 3 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत की अवधि शुक्रवार को पांच दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सीबीआई ने यह कहते हुए न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग की थी कि जांच अभी लंबित है। सीबीआई ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध

लोकसभा में लगे राहुल गांधी माफी मांगो के नारे, नहीं चल सकी संसद

नईदिल्ली। संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लंदन में लोकतंत्र पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष उनसे माफी की मांग कर रहा है। सड़क से संसद तक यह मामला उठाया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही है। तो दूसरी ओर अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। विपक्ष की ओर से लगातार अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग की जा रही है। विपक्ष किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखा गया। गतिरोध की वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 2ः00 बजे के आसपास पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सदस्य लगातार राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे।

राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे फिर शुरू होने के मात्र एक मिनट में ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने को लेकर उन्हें 14 नोटिस मिले हैं। इनमें से नौ नोटिस कांग्रेस सदस्यों के थे। सभापति ने कहा कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता पर नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और वाम दलों के बिनय विश्वम और एलामारम करीम ने भी अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर नोटिस दिए थे। सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए सभापति ने शून्यकाल शुरू किया और इसके तहत आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का नाम पुकारा। इसी बीच सदन में हंगामा और शोरगुल शुरू हो गया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिये गये लोकतंत्र संबंधी बयान को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सोमवार को लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2ः15 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनके बयान लिए माफी मांग करते हुए नारेबाजी की तो विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी की मांग को लेकर नारे लगाए। कांग्रेस सदस्यों ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए एक बयान को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियो के उनसे जानकारी मांगने से जुड़े विषय को लेकर भी नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शोर-शराबा बंद करने और सदन चलने देने की अपील की।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। ये विपक्षी दल विभिन्न केंद्रीय एजेंसी के कथित दुरुपयोग और अडाणी समूह से जुड़े कथित घोटाले के मामले पर इस सत्र में सरकार को घेरने को लेकर एकजुट हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख सकें, इसके लिए मंगलवार का समय मांगा गया है। उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के आवास पर पहुंचने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। यात्रा को पूरा हुए 46 दिन हो गए और वे अब पूछ रहे हैं कि आप किससे मिले थे? लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े और उनसे (राहुल गांधी) मुलाकात की। अब कहा जा रहा है कि आप मिलने वालों की पहचान करिए।" खरगे के अनुसार, राहुल गांधी ने संबंधित टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में की है और पुलिस इस बारे में यहां पूछ रही है। उन्होंने दावा किया, "यह परेशान करने की कोशिश है। वे धमकाकर हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम डरने और कमजोर होने वाले नहीं हैं।"

संसद के एक बार फिर स्थगित होने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि 13 मार्च से जो ड्रामा चल रहा है, वो बिना प्रधानमंत्री के इशारे के नहीं हो सकता। आज एक बार फिर संसद को चलने नहीं दिया गया। हम क्या मांग रहे हैं? आजादी के बाद सबसे बड़े घोटाले की सिर्फ एक जेपीसी जांच। उधर सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि उन्हें (भाजपा) को डर है कि अगर जेपीसी जांच होगी तो अडानी और केंद्र सरकार के बीच की सांठगांठ का पर्दाफाश हो जाएगा और असली अपराधी लोगों के सामने आ जाएगा।

कर्नाटक में कांग्रेस ने भी दिखानी शुरू की अपनी ताकत

राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

बेंगलुरु। कर्नाटक में मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस भी वहां मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए आज पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे। उन्होंने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। खड़गे और राहुल गांधी ने बेलगावी में युवा क्रांति समागम का शुभारंभ किया।

इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, यहां के युवाओं ने कहा कि उन्हें यहां कोई नौकरी नहीं मिल रही है और लोगों ने शिकायत की कि यह सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, यह 40% कमीशन वाली सरकार है। आपको बता दें कि चुनावी मौसम को देखते हुए कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए चौथी गारंटी - युवा निधि की घोषणा की है। राहुल ने कहा कि 3,000/माह सभी बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए दिए जाएंगे। 1,500/माह सभी डिप्लोमा धारकों के लिए 2 साल के लिए होंगे। कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डेढ़ साल के भीतर 2.5 लाख खाली सरकारी पदों को भरना हमारा मुख्य काम रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक की भाजपा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। इस दौरान खड़गे ने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबों की आवाज़ का महत्व होगा। जहां ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं होगा।

राहुल पर मोदी सरनेम वाले बयान पर 23 को कोर्ट सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर एक विवादित बयान दिया था। इस मामले में 23 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है। राहुल पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज है। अधिवक्ता किरीट पानवाला ने बताया कि कोर्ट का जब आदेश पारित किया जाएगा तब कांग्रेस नेता भी अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें लोकसभा चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? राहुल के बयान को लेकर गुजरात में काफी विरोध हुआ था। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस मामले में शिकायत की थी। पूर्णेश ने दावा किया कि विवादास्पद टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में की गई थी, जिसने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था। वकीलों ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की।

खेल
प्रमुख समाचार

स्विस ओपन में जीत की राह पर लौटने उतरेगी पीवी सिंधु

बासेल। खराब फॉर्म से जूझ रही गत चैम्पियन पी वी सिंधु मंगलवार से यहां शुरू हो रहे स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के जरिये जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेंगी। पिछली बार उपविजेता रहे दुनिया के नौवे नंबर के खिलाड़ी एच एस प्रणय भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे जो आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप से दूसरे दौर में ही बाहर हो गए थे। पांचवीं वरीयता प्राप्त प्रणय को हालांकि पहले दौर में 2018 विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता चीन के शि युकी का सामना करना है जो बर्मिंघम में पिछले सप्ताह उपविजेता रहे। प्रणय एकल वर्ग में भारत के लिये लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आये हैं जबकि सिंधु और लक्ष्य सेन इस सत्र में लय हासिल करने के लिये जूझते रहे हैं।

चोट के कारण लंबे समय तक कोर्ट से दूर रहने के बाद अच्छे नतीजे नहीं आने से सिंधु ने अपने कोरियाई कोच पार्क ताए सांग से नाता तोड़ लिया था। वह पिछले सप्ताह चीन की झांग यि मान से हारकर पहले दौर में ही बाहर हो गई थी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु पहले दौर में स्थानीय खिलाड़ी जेंजिरा स्टाडेलमान से खेलेंगी। वहीं मलेशिया और इंडिया ओपन में शुरूआती दौर से बाहर हुए सेन ने पिछले सप्ताह चोउ तियेन चेन को हराया लेकिन दो बार के विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से हार गए। उनका सामना हांगकांग के ली चेयुक यू से होगा। भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत चीन के 23 वर्ष के वेंग होंग यांग के खिलाफ अभियान का आगाज करेंगे। आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल तक पहुंची त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना पहले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त अप्रियानी राहायू और सिति फाडिया सिल्वा रामाधंती से होगा। पुरुष वर्ग में सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की टक्कर क्वालीफायर से मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाली जोड़ी से होगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 361 अंक नीचे पहुंचा निफ्टी 17000 से फिसला

नई दिल्ली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 360.95 (-0.62%) अंकों की गिरावट के साथ 57,628.95 अंकों के लेवल पर जबकि निफ्टी 111.65 (-0.65%) अंक फिसलकर 16,988.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी और यहां से सेंसेक्स लगभग 554 अंक संभला दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 57,084 अंकों के लेवल तक फिसल गया था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इस दौरान बजाज फिनसर्व के शेयरों में चार प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग, मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी।

आईपीओ को लेकर सेबी ने 6 कंपनियों के पेपर किए वापस

नईदिल्ली। पेटीएम के आईपीओ की असफलता के बाद बाजार नियामक सेबी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम से जुड़े नियमों को लेकर अब सतर्कता बरत रहा है। बता दें की सेबी ने दो महीने में 6 कंपनियों के आईपीओ को वापस लौटा दिया है। इसमें ओरावेल स्टेज ट्रैवल टेक फर्म सहित छह कंपनियां शामिल हैं। सेबी ने इन कंपनियों को अपनी विवरण पुस्तिका को कुछ जरूरी बदलाव करने के बाद फिर से दाखिल करने को कहा है। बाजार नियामक ने ओयो के अलावा जिन कंपनियों के डीआरएचपी को वापस लौटाया है, उसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, घरेलू मोबाइल विनिर्माता लावा इंटरनेशनल, कनाडा स्थित फेयरफैक्स ग्रुप समर्थित एक फर्म, बीटबी (कंपनियों के बीच) भुगतान और सेवा प्रदाता पेमेंट इंडिया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया और एकीकृत सेवा कंपनी बीवीजी इंडिया शामिल हैं।

क्रेडिट सुइस बैंक को मिल गया है तारनहार

जेनेवा। स्विटजरलैंड के संकटग्रस्त बैंक क्रेडिट सुइस को तारनहार मिल गया है। इस बैंक के संकट में आने से ग्लोबल बैंकिंग प्रणाली में उथल-पुथल आ गई थी। इसे रोकने के उद्देश्य से स्विटजरलैंड की ही एक प्रमुख वित्तीय कंपनी यूबीएस क्रेडिट सुइस को लगभग 3.25 अरब डॉलर में खरीदेगी। क्रेडिट सुइस ने बीते गुरुवार को ही कहा था कि वह अपने शेयरों के गिरने के बाद स्विस सेंट्रल बैंक से 54 अरब डॉलर तक का कर्ज लेगा। हालांकि इससे भी बैंक के ग्राहक और निवेशक आश्वस्त नहीं हुए। इसके बाद स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने यूबीएस से संकटग्रस्त बैंक का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बरसेत ने कहा कि यह सौदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, "क्रेडिट सुइस का अनियंत्रित तरीके से पतन देश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता।"

जयंती चौहान ही संभालेंगी बिसलेरी का कारोबार

नई दिल्ली। बोतलबंद पानी सप्लाई करने वाली कंपनी बिसलेरी की नई बॉस बिसलेरी की चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान होंगी। रमेश चौहान ने ईटी के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जयंती चौहान बिसलेरी की प्रोफेशन टीम के साथ मिलकर इस कंपनी का संचालन करेंगी। उन्होंने कहा कि जयंती अब कंपनी का संचालन करेंगी, इसलिए अब हम अपने बिजनेस को बेचना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि जयंती चौहान कंपनी की वाइस चेयरपर्सन हैं। दरअसल बिसलेरी और टाटा के बीच कारोबार के अधिग्रहण को लेकर बात चल रही थी। लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्स लिमिटेड ने इसे खरीदने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। टाटा और बिसलेरी के बीच डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। टाटा से बात बिगड़ने के बाद बिसलेरी को उसका उत्तराधिकारी मिल गया।

छोटे देशों के साथ चीन की गलत आर्थिक नीति

डॉ. पीएस वोहरा

पिछले वर्ष श्रीलंका की आर्थिक कंगाली ने इस बात को जगजाहिर किया कि कैसे हंबनटोटा बंदरगाह के विकास के बहाने श्रीलंका चीन की बातों में आ गया और उसके कर्ज में इतना दब गया कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार की बहुत कमी हो गयी और देश में आर्थिक संकट आ गया। यह सच है कि लंबे अरसे से चीन अपनी वैश्विक ताकत बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास का सपना दिखा कर छोटे राष्ट्रों को लगातार निशाना बना रहा है। श्रीलंका के अलावा भी कई अन्य मुल्क परेशानियों से घिरे हैं। पाकिस्तान इन दिनों संकट में है और उसका कारण भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। इस योजना के लिए चीन द्वारा पाकिस्तान को करीब 62 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। पाकिस्तान आयात पर निर्भर रहने वाला मुल्क है। आज उसके पास तीन अरब डॉलर से भी कम विदेशी मुद्रा रह गयी है। पाकिस्तान अब लगातार विदेशी संस्थानों से कर्ज की गुहार लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 148 से अधिक देशों में चीन ने निवेश किया हुआ है। एक बात और समझने वाली है कि लगभग इन सभी देशों में परियोजनाओं का संचालन चीनी कंपनियां ही कर रही हैं। चीन द्वारा दिये गये कर्जों पर तुलनात्मक रूप से ब्याज की दरें विश्व बैंक, आइएमएफ या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक होती हैं।

चीन का मुख्य उद्देश्य अपनी वैश्विक ताकत को बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की सहायता विभिन्न छोटे राष्ट्रों को दी हुई है। जिन-जिन मुल्कों में चीन ने निर्माण योजनाओं को शुरू किया, लगभग सभी परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। इसके

पीछे एक मुख्य कारण यह है कि उन योजनाओं की लागत बहुत अधिक बढ़ गयी है। दूसरा कारण यह है कि उन परियोजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। अब स्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि इन देशों में इन परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है। इस कारण चीन के लिए भी अब आर्थिक संकट की आशंका पैदा हो गयी है।

विश्व पिछले कुछ समय से लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। शुरुआत महामारी से हुई थी। रूस और यूक्रेन की समस्या ने वैश्विक स्तर पर आपूर्ति शृंखला बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे सभी देशों के घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ गयी है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज नीतियों के कारण डॉलर तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत होता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव सभी देशों की मुद्रा पर पड़ा है। इससे आयात की लागत बढ़ी है। ऐसे में कई छोटे राष्ट्र, जो चीन की परियोजनाओं से खुशहाली का सपना देख रहे थे, वे अब आर्थिक दबाव में हैं तथा चीन को भुगतान करने में अक्षम हैं। चीन वर्तमान समय में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा इसका वर्तमान स्तर 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का है। पिछले तीन-चार दशकों में चीन ने अभूतपूर्व वृद्धि कर पूरे विश्व में निर्माण के क्षेत्र में अपने आपको एक ऐसी फैक्टरी के रूप में स्थापित कर लिया है, जिस पर सभी देशों की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने 1978 के आर्थिक सुधारों के बाद वास्तविक रफ्तार पिछली शताब्दी के अंत में पकड़ना शुरू कर लिया था, जो उसे पिछले दो दशकों से लगातार शिखर पर बनाये हुए है। वर्ष 1978 के सुधारों से पूर्व चीन में हर पांच में से चार आदमी कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे, जो आज व्यापार में संलग्न हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 65 राष्ट्र पूर्णतया चीन से आयात पर निर्भर हैं। अगर यह अंदेशा आने वाले समय में सही साबित होता है, तो निश्चित रूप से ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट होगा। इसके अलावा कई ऐसे छोटे मुल्क, जो चीन पर निर्भर रहकर आर्थिक विकास के सपने को देख रहे हैं, उनकी बदहाली भी चीन के लिए एक बड़ा आर्थिक घाटा साबित होने वाला है। इसलिए अब जरूरत है कि चीन आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को कुछ सीमित करे, अन्यथा वैश्वीकरण के इस दौर में चीन सभी मुल्कों के लिए एक बड़ी समस्या बन जायेगा।

ईडी से परेशान विपक्ष की एकता कब तक टिकेगी?

अजय सेठिया

संसद भवन के भीतर चल रही विपक्षी दलों की बैठकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की संभावनाएं जगाई हैं। हालांकि इन बैठकों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने बैठक में तो हिस्सा लिया, लेकिन 15 मार्च को जब सभी सांसदों के ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च की बात आई, तो एनसीपी पीछे हट गई। ईडी निदेशक को लिखी गई चिट्ठी पर भी एनसीपी ने दस्तखत नहीं किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि चार राज्यों में कांग्रेस की जड़ों में मठ्ठा डालने वाली आम आदमी पार्टी उनकी बुलाई गई बैठकों में शामिल होने लगी है। कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही समाजवादी पार्टी भी बैठक में आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी ममता-केजरीवाल-केसीआर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। अखिलेश अभी कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इतना ही नहीं अखिलेश यादव भाजपा और कांग्रेस को एक बता रहे हैं। 17 मार्च को सपा अपना अधिवेशन पश्चिम बंगाल में करने जा रही है और अखिलेश कोलकाता में ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर और केजरीवाल का एक अलग मोर्चा बनता दिख रहा है। हालांकि टीवी डिबेट में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के प्रवक्ता किसी न किसी तरह की विपक्षी एकता हो जाने की संभावना जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बड़ा जोखिम उठाने के मूड में हैं, इसलिए बजट सत्र के पहले भाग में उन्होंने चुटकी लेते हुए लोकसभा में कहा था कि ईडी ने विपक्षी एकता करवा दी है। यही सच है, क्योंकि जैसे ही ईडी ने मनीष सिसोदिया पर हाथ मारा, आम आदमी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में पहुंच गये। जबकि कांग्रेस ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि शराब घोटाले की पूरी जांच की मांग भी की है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने साफ़ कहा है कि वह कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं जाएगी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी उनकी नेता ममता बनर्जी पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में कहा था कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्होंने अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ममता की चुप्पी का कारण यह है कि अडानी के मुद्दे पर ममता और मोदी में युद्धविराम हो गया है। इस संबंध में प्रमाण देते हुए चौधरी ने कहा था कि ताजपुर पोर्ट बनाने के लिए ममता का अडानी ग्रुप के साथ एमओयू साईन हो चुका है। अभी संसद में जो भी विपक्षी एकता दिख रही है, उसका कारण अडानी और ईडी ही हैं। विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है, इसलिए इसे संसद के बाहर विपक्षी एकता की संभावना के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। संसद के भीतर अडानी और ईडी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ विधानसभा चुनावों में गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं। अरविन्द केजरीवाल ने पिछले एक हफ्ते में इन सभी राज्यों में दौरा किया और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया। इन राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो गोवा और गुजरात की तरह कांग्रेस का बंटाधार करेगी और भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। सच यह है कि आम आदमी पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके कारण विपक्षी वोट बंटते हैं और भाजपा को फायदा होता है।

संसद को सड़क बनाने में तुले हैं राजनेता

ललित गर्ग

संसद की कार्रवाई को बाधित करना एवं संसदीय गतिरोध आम बात हो गयी है। यही स्थिति संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में देखने को मिल रही है, इस सत्र को शुरू हुए पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में हंगामे और नारेबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। जहां सत्तापक्ष संसद में अपनी इस मांग पर जोर दे रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो कुछ कहा, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वहीं कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल अदाणी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने पर अड़े हुए हैं और संसद नहीं चलने दे रहे हैं। विरोध प्रकट करने का असंसदीय एवं आक्रामक तरीका, सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तकरार और इन स्थितियों से उत्पन्न संसदीय गतिरोध लोकतंत्र की गरिमा को धुंधलाने वाले हैं। अपने विरोध को विराट बनाने के लिये सार्थक बहस की बजाय शोर-शराबा और नारेबाजी की स्थितियां कैसे लोकतांत्रिक कही जा सकती हैं?

कितना दुखद है कि एक दिन भी संसद में ढंग से काम नहीं हो सका है। विवादों का ऐसा सिलसिला छिड़ गया है, जो लगता नहीं कि आसानी से खत्म होगा। विवाद संसद में भी होते हैं और सड़क पर भी। लेकिन संसद को सड़क तो नहीं बनने दिया जा सकता? वैसे, भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर पहले भी आए हैं, जब परस्पर संघर्ष के तत्व ज्यादा और समन्वय एवं सौहार्द की कोशिशें बहुत कम नजर आई हैं। स्पष्ट है कि यदि दोनों पक्ष अपने-अपने रवैये पर अडिग रहते हैं तो संसद का चलना मुश्किल ही होगा। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि बजट को बिना बहस के पारित कराना पड़े। यह ठीक नहीं होगा, लेकिन संसद तभी चल सकती है, जब दोनों पक्ष अपना-अपना हठ छोड़ेंगे। फिलहाल इसके आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यह तय है कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगने वाले। एक ओर जहां मल्लिकार्जुन खरगे यह साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगने वाले, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य नेता भी यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उनके नेता ने लंदन में वैसा कुछ कहा ही नहीं, जैसा बताया जा रहा है। इस तरह की द्वंद्वपूर्ण स्थितियों से तो संसदीय मर्यादाएं बार-बार भंग होती रहेगी एवं संसद में हुड़दंग मचाने, अभद्रता प्रदर्शित करने एवं हिंसक घटनाओं को बल देने के परिदृश्य बार-बार उपस्थित होते रहेंगे। गलत को गलत न मानने के हठ को कैसे स्वीकार्य किया जा सकता है? यह कैसी हठधर्मिता है कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले राहुल के माफी मांगने पर कांग्रेस तैयार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है।

संसद का यह सत्र इसलिये भी आक्रामक बना हुआ है कि पक्ष एवं विपक्ष दोनों की ही नजरों में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। इसीलिये इसके आसार नहीं कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, वैसे ही इसकी भी कोई संभावना नहीं कि मोदी सरकार अदाणी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका एक कारण तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही छह सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा कर चुका है और दूसरा यह कि वित्तीय मामलों में अब तक गठित संयुक्त संसदीय समितियों ने जांच के नाम पर या तो लीपापोती की है या फिर दलगत राजनीति। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदाणी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की विपक्ष की मांग का मुख्य उद्देश्य इस मामले को अगले आम चुनाव तक जिंदा रखना है। चूंकि सरकार विपक्ष के इस इरादे को भांप चुकी है, इसलिए वह उसकी मांग पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। कैसी विचित्र एवं त्रासद स्थिति है कि सबके सामने देश नहीं, सत्ता का स्वार्थ है। देश को बनाने एवं विकास की रफ्तार देने के लिये बजट का लोकतांत्रिक तरीकों से पारित होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि बजट को बिना बहस के पारित कराना पड़े। यह ठीक नहीं होगा, लेकिन संसद तभी चल सकती है, जब दोनों पक्ष अपना-अपना हठ छोड़ेंगे। फिलहाल इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह- भारतीय राजनीति में ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे जो इन तीनों स्थितियों से बाहर निकलकर जी रहे हैं। पर जब हम आज राष्ट्र की विधायी संचालन में लगे अगुओं को देखते हैं तो किसी को इनसे मुक्त नहीं पाते। आजादी के बाद सात दशक बीत चुके हैं, लोकतंत्र के सारथियों की परिपक्वता नहीं पनप पा रही हैं, साफ चरित्र जन्म नहीं ले पाया है, लोकतंत्र को हांकने के लिये हम प्रशिक्षित नहीं हो पाये हैं। उसका बीजवपन नहीं हुआ या खाद-पानी का सिंचन नहीं हुआ। आज आग्रह पल रहे हैं-पूर्वाग्रहित के बिना कोई विचार अभिव्यक्ति नहीं और कभी निजी और कभी दल स्वार्थ के लिए दुराग्रही हो जाते हैं। कल्पना सभी रामराज्य की करते हैं पर रचा रहे हैं महाभारत। महाभारत भी ऐसा जहां न श्रीकृष्ण है, न युधिष्ठिर और न अर्जुन। न भीष्म पितामह हैं, न कर्ण। सब धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनि बने हुए हैं। न गीता सुनाने वाला है, न सुनने वाला।

विपक्षी दल अनावश्यक आक्रामकता का परिचय देंगे तो सरकार उन्हें उसी की भाषा में जवाब देगी। इसके चलते अब संसद के सत्रों के दौरान कहीं अधिक शोर-शराबा होने लगा है। ऐसा होने का सीधा मतलब है कि संसद में विधायी कामकाज कम, हल्ला-गुल्ला ज्यादा होता है। कायदे से इस अप्रिय स्थिति से बचा जाना चाहिए। यह एक बड़ा सच है कि लोकतंत्र एक जटिल व्यवस्था है और इसे बार-बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। निश्चित ही, लोकतंत्र पर देश में या देश से बाहर टिप्पणी करते समय व्यापकता में विचार करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के किसी भी बड़े नेता की टिप्पणियों में शासन-प्रशासन का इतिहास और भूगोल, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के स्वर होने ही चाहिए। आशा की जाती है कि लोकतंत्र पहले भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरकर निखरा है और लोगों को यही उम्मीद होगी कि इस बार भी निखरेगा। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र को हांकने वाले लोग आखिर कब परिपक्व होंगे? कब भारतीय लोकतंत्र इन दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण त्रासदियों से बाहर आयेगा? संसदीय लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं, वह पक्ष-विपक्ष की शर्तों से नहीं, आपसी समझबूझ, मूल्यों एवं आपसी सहमति की राजनीति से चलता है। एक तरह से साबित हो गया, भारतीय राजनीति में परस्पर विरोध कितना जड़ एवं अव्यावहारिक है। राजनीति की रफ्तार तेज है, लेकिन कहीं ठहरकर सोचना भी चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा में थोड़ा-सा समय विरोध-प्रतिरोध के लिए हो और ज्यादा से ज्यादा समय देश के तेज विकास एवं देश निर्माण की चर्चाओं एवं योजनाओं में लगे। हमारे राजनेता जब टकराव पर उतरते हैं, तो शायद नहीं सोचते कि देश में क्या संदेश जा रहा है। संसद के इस सत्र में केवल बजट पर ही बहस नहीं होनी है, बल्कि कम से कम तीन दर्जन विधेयक भी पारित होने हैं। इनमें से कई अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। यदि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते प्रस्तावित विधेयक पारित नहीं हो पाते तो यह एक तरह से राष्ट्र की राह रोकने वाला काम होगा। उचित यह होगा कि सत्तापक्ष और विपक्ष यह समझें कि संसद में गतिरोध की स्थिति पैदाकर वे जनता को निराश करने का ही काम कर रहे हैं। क्या भारतीय राजनीति में आज इतनी शालीनता भी नहीं बची कि अपनी गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर आगे ऐसी त्रासद घटनाओं के न होने के लिये संकल्पित हो।

प्रसंग — मेरा अपना कुछ नहीं

पारसी धर्मगुरु रवि मेहर के तीन पुत्र थे। वे तीनों के तीनों महामारी की चपेट में आ गये और अच्छी दवा के अभाव में जीवित न रह सके। मेहर उस समय बाहर गये हुए थे। सन्ध्या समय जब वे घर आये, तो उन्हें बच्चे दिखायी न दिये। उन्होंने सोचा, शायद सो गये होंगे। भोजन करते समय उन्होंने पत्नी से पूछा, क्या आज बच्चे जल्दी सो गये ? पत्नी ने इसका उत्तर दिये बिना उनसे कहा, स्वामी! कल हमने पड़ोसी से जो बर्तन लिये थे, उन्हें माँगने के लिए पड़ोसी आये थे। मेहर ने कहा, बर्तन उनके थे, इसलिए लेने आये थे। परायी वस्तु का मोह हम क्यों करें ? पत्नी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैंने उन्हें वे बर्तन दे दिये।

भोजन के उपरान्त सन्त को बच्चों का फिर स्मरण हो आया और उन्होंने पत्नी से उनके बारे में पूछताछ की। तब पत्नी उन्हें शयन कक्ष में ले गयी और उसने चारपाई के नीचे रखे तीनों बच्चों के शव दिखाये। यह देखते ही सन्त फूट-फूटकर रोने लगे। तब पत्नी बोली, स्वामी! आप अभी-अभी तो कह रहे थे कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु लेना चाहे, तो हमें वह वस्तु दे देनी चाहिए और उसके लिए दु:ख नहीं करना चाहिए, लेकिन आप स्वयं ही यह भूल रहे हैं। बच्चे भगवान् ने दिये थे, सो उन्होंने ले लिये, फिर हम उनके लिए क्यों वृथा शोक करें ?

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2000 गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।
2002 ब्रिटिश छात्रा अमांडा डाउलर को सरे के वाल्टन-ऑन-थेम्स में होमफ्रॉम हीथसाइड स्कूल के रास्ते में अपहरण कर लिया गया था।
2006 एक हथौड़ा का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने थाइलैंड के बैंकॉक में इरान श्राइन में फ्रा फ्रॉम की प्रतिमा को तोड़ दिया और बाद में दर्शकों द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया।
2008 वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर महासागर होने के नये साक्ष्य प्राप्त किये।
2010 अफगानिस्तान में हेलमंड प्रांत के गेरेश में हुआ एक आत्मघाती बम हमला, दस लोगों की मौत और सात घायल हो गए।
2011 त्रिपोली में आतंकवादी नेता मुअम्मर गद्दाफी के परिसर को लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की तीसरी रात के दौरान अधिक बमबारी के साथ लक्षित किया गया था जिसने गद्दाफी की पूरी आतंकवादी श्रृंखला को हिला दिया था।
2011 बोस्टन, मैसाचुसेट्स में ब्रिघम और महिलाओं के अस्पताल में सर्जन ने पहले पूर्ण चेहरे का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

मैत्रेय्युपनिषद् (भाग-05)

गतांक से आगे...

(अन्त: स्थित ब्रह्म) मैं हूँ और (बाह्य स्थित) पर (ब्रह्म) भी मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उत्पत्ति हूँ, समस्त लोकों का गुरु हूँ और सभी लोकों में जो भी कुछ है, वह मैं ही हूँ। सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ तथा परम तत्त्व भी मैं ही हूँ। मैं सदैव (विद्यमान रहता हूँ, मैं नित्य हूँ एवं मलरहित भी मैं ही हूँ। मैं विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हूँ, मैं विशेष हूँ, सोम मैं हूँ, सभी कुछ मैं ही हूँ। मैं शुभ हूँ, शोकरहित हूँ, सम हूँ तथा चैतन्य भी मैं ही हूँ। मैं मान एवं अपमान से रहित हूँ, निर्गुण (गुणरहित) हूँ, मैं ही शिव हूँ, द्वैत एवं अद्वैत के भाव से रहित हूँ, सुख तथा दु:ख आदि द्वन्द्वों से रहित हूँ तथा वह (ब्रह्म) मैं ही हूँ।

भाव- अभाव अर्थात् उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ। भासा (प्रकाश) से अलग हूँ, किन्तु प्रकाश भी मैं ही हूँ। मैं शून्य और अशून्य रूप हूँ तथा मैं ही सुन्दर और असुन्दर भी हूँ। तुल्य- अतुल्य अर्थात् समता एवं विषमता से रहित हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ एवं सदाशिव हूँ। मैं सर्व- असर्व की कल्पना से रहित हूँ, सात्त्विक हूँ और मैं सदैव (विद्यमान रहने वाला) हूँ। मैं एक संख्या विहीन (अद्वैतरहित) और दो संख्या रहित (द्वैतरहित) हूँ, सत् और असत् के भेद से रहित हूँ तथा मैं संकल्प से रहित हूँ।

मैं विविधता से रहित तथा अखण्ड आनन्द स्वरूप हूँ । न मैं (अहं रूप) हूँ और अन्य भी नहीं हूँ। मैं आश्रय - निराश्रय से रहित हूँ, मैं आधार रहित हूँ, बन्ध एवं मोक्ष से भी रहित हूँ तथा मैं ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं चित्त आदि सभी से रहित हूँ, मैं परात्पर (ब्रह्म) हूँ। मैं सर्वदा विचार रूप हैं. साथ ही विचार से परे भी हूँ। अकार, उकार एवं मकार रूप सनातन मैं ही हूँ। मैं ध्याता, ध्यान एवं ध्येय से परे भी हूँ। मैं सर्वत्र पूर्णरूप हूँ, सच्चिदानन्द के लक्षणों से युक्त हूँ। सम्पूर्ण तीर्थों का स्वरूप भी मैं हूँ और परमात्म स्वरूप कल्याणकारी भगवान् शिव भी मैं ही हूँ । मैं लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूँ तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूँ। मैं ही प्रमाण, प्रमेय और मैं इस संसार का सर्वद्रष्टा नहीं हूँ।

मैं आँख आदि समस्त इन्द्रियों से रहित हूँ। मैं ही वृद्धि को प्राप्त करता हुआ, ज्ञानवान्, प्रसन्न एवं हर (पापों को हरने वाला) हूँ । मैं सभी इन्द्रियों से रहित हूँ, तब भी समस्त कर्म करने वाला मैं स्वयं ही हूँ। समस्त वेदान्त द्वारा सर्वदा तृप्त एवं सर्व सुलभ मैं ही हूँ। मैं आनन्द एवं शोक रूप हूँ, सर्वदा मौन रहने का फल रूप हूँ। नित्य चिद् रूप हूँ तथा मैं ही सच्चिद् रूप भी हूँ। जो कुछ भी है, मैं उससे रहित हूँ, मैं अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूँ।

क्रमश:...

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस आज

हर साल 21 मार्च को पेड़ों के महत्व के विषय में जन-जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस या अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। जंगलों के बचाए रखने के लिए वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं आम बैठक में 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया।

बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी पेड़ों के महत्व के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने पर अपनी सहमति दी, तभी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने की

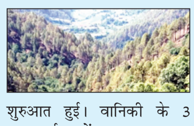

शुरुआत हुई। वानिकी के 3 महत्वपूर्ण तत्वों- सुरक्षा, उत्पादन और वन विहार के बारे में लोगों को जानकारियां देने के लिए उसी साल बाद में 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में चुना गया। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल वस्तुत: एक ऐसा जीवित समुदाय होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, पेड़-पौधे, कीट-पतंगे एक-दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं। पर्यावरणविदों की शिकायत है कि पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से मनुष्य ने अपने लालच की पूर्ति के लिए जंगलों का वध करना शुरू किया है, उससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना जैसी विकट समस्याएं शुरू हुई हैं।

अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो समस्त प्रकृति व जीव खतरे में पड़ जाएंगे। किसी वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वह उसे 16 बड़े-बड़े पेड़ों से मिल सकती है। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से उनकी संख्या दिनों दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। वर्तमान समय में वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सीएफसी जैसी जहरीली गैसों को सोखकर धरती पर रह रहे असंख्य जीवधारियों को प्राणवायु ऑक्सीजन देने वाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पृथ्वी को इस घोर संकट से बचाने के लिए विश्व की जनसंख्या अगर 1-1 पेड़ लगाए तो पृथ्वी को फिर से हरा-भरा बनाया जा सकता है। हमने अपने लाभ के लिए पेड़ काट दिए, लेकिन जंगल कुदरत द्वारा दिए गए वे उपहार हैं, जो हमें जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम समस्याओं से बचने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। दुनिया की आधे से ज्यादा वनस्पति, जंतु तथा कीट प्रजातियां इन्हीं ऊष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती हैं। लेकिन बड़ी तेजी से काटे जा रहे पेड़ों के कारण सभी का जीवन खतरे में पड़ रहा है।

रूस और अमेरिकी संबंध और बिगड़े तो विश्व युद्ध का खतरा

अशोक मधुप

एक साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटों के दखल को देख शायद रूस ने अब इनसे ही सीधे सुलटने का निर्णय ले लिया है। वह इस तरह की पहले से इसकी चेतावनी देता भी रहा है। लगता है कि इसकी शुरुआत उसने कालासागर में अमेरिकी ड्रोन को मार कर कर दी है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। अपने इरादे भी बता दिए हैं। घटना को लेकर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका रूस की जासूसी कर रहा है। इसी वजह से ये घटना हुई। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका ने कोई उकसावे की कार्रवाई की तो रूस भी उसका %उचित जवाब% देगा।

एक साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब यह साबित हो गया कि नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को सबक सिखाना चाहते हैं। उसे तोड़ना चाहते हैं। उनका इरादा रूस की अकड़ खत्म करने का है। यह खुद तो नहीं लड़ रहे किंतु युद्धरत यूक्रेन की अस्त्र-शस्त्र और अन्य प्रकार की पूरी क्षमता से मदद करने में लगे हुए हैं। रूस भी हालत को समझ गया है। उसने पीठ पीछे की कहानी को आगे करने का निर्णय लिया। इसी के तहत रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ते अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। उसकी ये कार्रवाई बताती है कि उसने अमेरिका और नाटो देशों से अब सीधे निपटने का फैसला कर लिया है। अच्छा है कि नाटो अब भी

संभाल जाए। सुधर जाए। रूस के दुश्मन यूक्रेन की परोक्ष और अपरोक्ष रूप से की जाने वाली मदद बंद कर दें। ऐसा न होने पर वह नाटो देशों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर सकता है।

यूक्रेन एक छोटा-सा देश है। रूस जैसी महाशक्ति से उसका कोई मुकाबला नहीं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के प्रयास में लगा था। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो गठबंधन में शरीक न हो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते रहे हैं। पुतिन की सदा मंशा रही कि वो रूस को साल 1991 से पहले यानि सोवियत संघ के विघटन से पहले वाले स्वरूप में वापस लेकर आएं। यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाए। वह ऐसा नहीं कर पाए। उधर यूक्रेन नाटों में शामिल होने के प्रयास में लग गया। इससे उन्हें लगा कि यदि ऐसा हो गया तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आ जाएंगी। यूक्रेन की और रूस की सीमा सटी है। नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आकर रूस के लिए परेशानी ही पैदा करेंगी। साथ ही उसकी यूक्रेन के रूस में मिलाने की योजना भी धूसरित हो जाएगी।

यूक्रेन पूरी क्षमता से नाटो में शामिल होने के प्रयास में लगा था। रूस के मना करने की अपील का उस पर असर नजर नही आ रहा था। ऐसे में उसे सबक सिखाने में लिए रूस ने ये हमला किया। उसने इसे छोटा सैन्य आपरेशन नाम दिया। रूस ने हमला ये सोचकर किया कि यूक्रेन के नाटों में शामिल होने के बाद नाटो देश उसका साथ देंगे, पहले नहीं, किंतु एक साल से चल रहे युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका और नाटो देश खुद युद्ध नहीं लड़ रहे, अपितु वे यूक्रेन को युद्ध लड़ा रहे हैं। मदद कर रहे हैं। खुद युद्ध के मैदान में नही हैं किंतु हथियार और गोला बारूद उनका है। सिर्फ लड़ने वाले उनके सैनिक नहीं हैं। वे सिर्फ यूक्रेन के जवान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 30 देशों ने भारी तादाद में यूक्रेन को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराईं। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन को विध्वंसकारी टैंक जैसे- %चैलेंजर 2 टैंक% और %लेपर्ड 2 टैंक% यूक्रेन को मुहैया कराये जाएंगे। यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर भेजे हैं। इसके अलावा, अमेरिका ने यूक्रेन को 59 ब्रेडली इन्फैंट्री लड़ाकू विमान भेजे हैं। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका लगातार अपने हथियारों का जखीरा यूक्रेन को दे रहा है। गौरतलब है कि रूस लगातार यह बात कहता आया है कि यह युद्ध यूक्रेन के अलावा अमेरिका भी लड़ रहा है।

रूस लंबे समय से अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन की मदद की तो ठीक नहीं होगा। वह मदद को सीधा अपने पर हमला मानेगा। कई बार वह परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की धमकी भी देता रहा है। यह भी कहा है कि किसी देश की सैटलाइट उनके देश की जासूसी करती मिली, तो वह उस सैटलाइट को मार गिराएगा। अमेरिका और नाटो देशों की कोशिश थी कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर कर दिया जाए। किंतु एक साल बीतने पर भी ऐसा नहीं हो सका। रूस पेट्रोलियम उत्पाद का बड़ा केंद्र है। यह यूरोपियन देशों को पेट्रोलियम पदार्थ गैस आदि की आपूर्ति करता रहा है। युद्ध के दौरान उसने भारत और चीन को सस्ते पेट्रोलियम उत्पाद बेचकर अपनी आर्थिक हालत मजबूत बनाए रखी। इसका अमेरिका और नाटो देशों ने विरोध किया। भारत ने तो साफ कर दिया कि वह अपनी जरूरत का सामान उस देश से लेगा, जिससे उसे लाभ होगा। उसके हित सिद्ध होंगे। चीन के बारे में दुनिया जानती है, इसलिए उसने भी किसी की नहीं सुनी। रूस की मजबूती का एक कारण दुनिया के कई देशों को शस्त्रों की आपूर्ति भी है। वह लगातार जारी है। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध रूस की जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा। युद्ध यूक्रेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है। युद्ध का मैदान बना होने के कारण बर्बाद यूक्रेन हो रहा है, रूस नहीं। रूस ने युद्ध के दौरान भारत को एस 400 मिसाइल डिफैंस सिस्टम की तीसरी यूनिट ही नहीं दी, बल्कि वह पुराने करार के अनुरूप भारत समेत अन्य देशों को शस्त्र दे रहा है। उसके कल कारखाने पहले की तरह की काम कर रहे हैं। अभी रूस और ईरान के बीच 24 सुखोई विमान बेचने का सौदा हुआ है। उधर रूस भारत में सुपर सुखोई सुपर जेट और उसके कलपुर्जे बनाने की बात चला रहा है।

गांधी आज

चरखे के संबंध में खास खयाल

चरखे के विषय में अनेक टीकाएं होती हैं, उनकी जड़ में हैं चरखे के संबंध में अनेक गलत धारणाएं। वे धारणाएं क्या हैं यह नीचे के उत्तरों से मालूम हो जाएगा। चरखा मिलों की प्रतिद्वंद्विता नहीं करता; कर सकता भी नहीं पर मिलें चरखे से स्पर्धा करती हैं, और उस हद तक वे बंद कराने योग्य हैं। जिस सशक्त मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे समय का उपयोग करने भर को काम मिल जाता है उसे वह काम करने से रोकना चरखे का उद्देश्य नहीं है। चरखा कुल मिलाकर देश के धन की अवश्य वृद्धि करता है, और पूरी मज़दूरी दी जाय तो चलानेवाले का गुजर करा सकता है। पर चरखे से कोई गुण है क्योंकि इससे धन का समान बँटवारा अपने आप ही हो जाता है। 15. हिन्दुस्तान के किसानों का आज खेती से बचनेवाला छ: महीने का समय निरर्थक जाता है जिसके परिणामस्वरूप बेकारी और गरीबी का टेढा प्रश्न उपस्थित होता है। इस प्रश्न का तात्कालिक, व्यावहारिक और स्थायी इलाज चरखा है, इतना अवश्य चरखावादियों का दावा है। चरखे से आमदनी भले ही फूटी कौड़ी के बराबर ही होती हो, पर किसान का तो आधा साल बेकार जाता है जिसमें उसे फूटी कौड़ी की भी आमदनी नहीं होती और उसे बेकारी का रोग लग जाता है। इन दो बातों के लिए हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्र में चरखे का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऊपर जो यह कहा गया है कि चरखे से बेकारों को नाम की ही सही पर कुछ आमदनी तो हो सकती है वह आत्म-संतोष के लिए नहीं बल्कि चरखे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कहा गया है। सच पूछिए तो क्या चरखे की, क्या किसी दूसरे श्रम की मज़दूरी नहीं के बराबर रहे, यह संतोषजनक स्थिति नहीं। इस संबंध में अधिक विचार स्वावलंबी और व्यापारी खादी में किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

छुट्टी के दिन भी जमा कर सकेंगे टैक्स

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर में अब

सभी वार्डों के करदाता नागरिकों के लिए बेहतर सुविधा लागू किया है। 31 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला रहेगा। सभी 10 जोनों के राजस्व विभाग कार्यालय और सदर काउंटर छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। नगर निगम के सभी 70 वार्डों में आम दिनों की तरह छुट्टी में कार्यालय खुला रहेगा। करदाता नागरिक अवकाश के दिन में भी अपने वार्ड से सम्बंधित जोन कार्यालय में जाकर नगर निगम राजस्व विभाग को संपत्तिकर, यूजर चार्ज, निगम करों की भुगतान कर सकते हैं। निगम करों की भुगतान ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। शनिवार और रविवार सहित सभी शासकीय अवकाश के दिनों में सभी वार्डों में वार्डवार अवकाश कालीन राजस्व वसूली शिविर लगाये जा रहे हैं। नागरिक वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में जाकर निगम को अपने घर के पास सरलता से भुगतान कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ की तीरंदाज मधु वेदवान ने जीता कांस्य पदक

रायपुर। गुजरात के एकता नगर में 9 से 18

मार्च तक 42वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय रेलवे की तीरंदाजी टीम की उम्दा प्रस्तुति देखने को मिला। जिसमें तीरंदाजी टीम के मधु वेदान ने कास्य पदक जीत कर अपना नाम किया। जिसमें रेलवे की 22 महिला खिलाडियों में से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की तीरंदाज मधु वेदवान भी शामिल थी। वें बिलासपुर के मुख्यालय भंडार विभाग में जूनियर क्लर्क के पद कार्यरत है। भारतीय रेलवे के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हमेशा से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है। खिलाड़ी ने देश के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भी नाम रौशन किया है। साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे की अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय रेलवे की तीरंदाजी टीम और उसमें शामिल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन और उपलब्धि पर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अधिकारियों व साथी खिलाड़ियों/कर्मचारियों ने बधाई दिया।

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान : बूथों पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने योजनाओं को बताया

कोरबा। एनएसयूआई ग्रामीण ने ग्राम नोनबिर्रा से रविवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। मतदान बूथों पर पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य शासन की योजनाओं के बारे में बताया। केन्द्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। एनएसयूआई के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मनमोहन राठौर के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में संगठन के निगरानी समिति सदस्य शिव यादव व कटघोरा विधानसभा अध्यक्ष मयंक राठौर का सहयोग रहा। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों में पहुंचकर राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों को लाभ उठाने प्रेरित किया। अभियान के उद्देश्यों को लोगों के सामने रखा।

नगर आगमन पर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा का हुआ स्वागत

सक्ती। नगर के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा का एवं उनके साथ जा रहे समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों का शहर के अग्रसेन चौक में आतिशबाजी फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया ज्ञात हो कि श्री शर्मा खरसिया में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण समारोह में शामिल होने खरसिया जा रहे थे। वही शहर के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन चौक पर स्वागत आयोजन किया जिसमें समाज के साथ अन्य समाज के काफी लोग भी शामिल हुये। समाज के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा बाबा, मदन मोहन शर्मा ,पंडित राधेश्याम शर्मा, चंद्रभूषण तिवारी, मधुसूदन शर्मा, सजन शर्मा,कमल शर्मा,मनोज दुबे , राजेश शर्मा ठेकेदार, पीयूष राय, राजेश शर्मा घड़ी, ऋषिकेश चौबे , पत्रकार राज शर्मा , जगत शर्मा ,विष्णु शर्मा, सुमित शर्मा, उमेश शर्मा बंटी, अभिषेक शर्मा,दीपक शर्मा, गोविंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग अधिक संख्या में शामिल रहे।

मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर की संचालन समिति गठित

कोरबा। चैतुरगढ़ स्थित आदिशक्ति मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर के संचालन समिति का गठन कर लिया गया है। समिति के प्रशासक पाली एसडीएम नियुक्त किए गए। 15 सदस्यीय टीम में उपाध्यक्ष पाली-तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा, गौ-सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा, राज्य श्रम कल्याण मंडल के सदस्य नवीन सिंह ठाकुर, पाली के नायब तहसीलदार, जनपद पाली के सीईओ, ग्राम पंचायत लाफ के सरपंच लक्ष्मीनारायण सिंह समेत अन्य शामिल हैं।

कबीरधाम जिले में दो दिवसीय भोरमदेव महोत्सव का हुआ आगाज

भोरमदेव महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीप प्रज्जवलित कर वैदिक मंत्रोचार के साथ हुआ विधिवत शुभारंभ

कवर्धा। सतपुड़ा पर्वत की मैकल पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरे सुरम्यवादियों में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के प्रांगण में वर्षो से आयोजित हो रहे भोरमदेव महोत्सव की परंपरा को कायम रखने जिला प्रशासन द्वारा दो दिवसीय भोरमदेव महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दीप प्रज्जवलित कर वैदिक मंत्रोचार के साथ भगवान भोरमदेव की पूजा अर्चना और छत्तीसगढ़ महतारी के तैल्यचित्र पर पुष्प अर्पित कर छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध मंदिरों और आदिवासी बैगा समाज के पुजारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंच पर बुढ़ा महादेव मंदिर के पुजारी श्री मनहरण दुबे, मां दन्तेश्वरी मंदिर के पुजारी श्री अजय राजपूत,

मां चण्डी मंदिर के पुजारी श्री तिहारी चन्द्रवंशी, श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के पुजारी श्री चन्द्रकिरण तिवारी, ग्राम कामठी पंण्डरिया के श्री परसराम मरकाम और ग्राम भुरसीपकरी बोड़ला के श्री लमतू सिंह बगदरिया, पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, जनपद अध्यक्ष लीला धनुक वर्मा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह, डीएफओ श्री चुड़ामणी सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल उपस्थित थे।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए, समस्त पुजारियों ने महोत्सव में विशेष रूप से आमंत्रित करने पर महोत्सव के आयोजक भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट, जिला प्रशासन तथा सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर ने कहा कि पिछले वर्ष के परम्परा के अनुरूप इस वर्ष भी जिले के पुजारियों अतिथि के रूप में आशिर्वाद देने पहुंचे है। भोरमदेव महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति सहित भारतीय परम्पराओं पर अधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने कलाकार आए है। छत्तीसगढ़ की लोक परम्परा विख्यात है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की परम्परा को सहजने का काम किया जा रहा है। महोत्सव में भी छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोकगीत को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा देश के साथ-साथ विदेशों में भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परम्परा के महत्व को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने विशेष अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए भोरमदेव महोत्सव की आरंभ से लेकर वर्तमान दौर तक पूरी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटन और जन आस्था के रूप में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। इस मंदिर की ख्याति देश के अलग-अलग राज्यों तक फैली हुई है। यहां साल भर विदेशी, देशी तथा घरेलु पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के रूप में आना होता है। बाबा भोरमदेव मंदिर में प्रत्येक वर्ष होली के बाद कृष्णपक्ष के तेरस और चौदस को महोत्सव मानने की यहां परम्परा रही है।

भाजपा का मकसद आरक्षण नहीं, राजनीति : भगत

आदिवासियों को आगे कर प्रदर्शन करते थे, अब मुंह पर ताला

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, जब तक आरक्षण पारित नहीं हुआ था, भाजपाई तब तक आदिवासियों को आगे कर कलेक्टर का घेराव और सभा करते थे। जब से विधानसभा में पारित हुआ है, तब से इनके मुंह पर ताला बंद हो गया है। ये न राज्यपाल से मिलते हैं, न स्टेटमेंट देते हैं, न ज्ञापन देते हैं, न कोई प्रदर्शन करते हैं। कहा कि, इनकी असलियत खुल कर सामने आ गई है। ये आरक्षण का लाभ दिलाना नहीं, बल्कि पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। मंत्री भगत सोमवार को डोंगरगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं।

मीडिया से बात करते हुए मंत्री भगत ने पिछले दिनों चुनाव हारने पर अपनी मूंछ मुड़वाने वाले बयान पर भी बात की। कहा कि, इस बयान के पीछे लॉजिक भी है। उन्होंने कहा कि, जितना काम प्रदेश में कांग्रेस के शासन में हुआ है, उतना देश में कहीं नहीं हुआ। यहां किसानों, नौजवानों, आदिवासियों, महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा काम हर ओर से किया गया है। जनता सब जानती है और उसे पता है। यही लॉजिक है कि चुनाव हारने पर मूंछ मुंड़वाने की बात कही। कांग्रेस अगली बार फिर जीत रही है। हमारी सरकार ने निचले स्तर तक हर व्यक्ति के लिए काम किया है। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले डोंगरगढ़ पहुंचकर उन्होंने मां बम्लेश्वरी देवी की पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

इसके बाद वह लोधी समाज की ओर से ग्राम कोपेडीह में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

आरक्षण बिल विवाद : कांग्रेस विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायकों ने आज सोमवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुलाकात की । इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द आरक्षण बिल को पास किया जाए। आरक्षण बिल पास नहीं होने से राज्य में सरकारी भर्तियां नहीं हो रही हैं। इससे युवा वर्ग काफी परेशान है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है। इस दौरान एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस बिल को लेकर कार्रवाई चल रही है। समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें कोर्ट से लेकर जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे पर ये बिल पास कराकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में है। मामले में राजनीति की जा रही है।

भाजपा इन दिनों हवाई अड्डों-बंदरगाहों को बेचने में व्यस्त : भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी को संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का फायदा मिले।

कांकड़ जिले के पटेल समाज महासम्मेलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इन दिनों भाजपा हवाई अड्डों और बंदरगाहों को बेचने में व्यस्त हैं। सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं। सभी सरकारी कारखाने बंद हो रहे हैं। कोई जगह नहीं बचेगी आप लोगों को नौकरी पाने के लिए। अगर बीजेपी इन इकाइयों को बेचती रहेगी तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा?

सीएम बघेल ने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित आरक्षण बिल, जो राज्य में कोटा की मात्रा को 76 प्रतिशत तक बढ़ा देगा, अभी भी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास लंबित है।

भूपेश बघेल ने कहा, मैंने वह बिल दिसंबर के महीने में भेजा था, तीन महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाही नहीं की गई है। बिल अभी भी राज्यपाल के कार्यालय के पास लंबित है। आरक्षण प्रस्ताव राजभवन में अटका हुआ है और भाजपा इसे रोक रही है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा को तुरंत एक जनगणना सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना आसान हो सके। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। इसे वर्ष 2021 में आयोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दो वर्षों से इसमें देरी हो रही है। हमारे लोगों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहा है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना और राज्य में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 76 प्रतिशत किए जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस नीत सरकार के बीच लंबे समय से टकराव है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकड़ जिले कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया।

आदिवासी अंचल में निर्बाध बिजली देने बढ़ाई 132 केवी सब स्टेशन की क्षमता

■ **250 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ, सवा चार करोड़ की लागत से लगा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर**

रायपुर। आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लगातार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आदिवासी क्षेत्र में विद्युत पारेषण प्रणाली को मजबूत करने विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पखांजूर स्थित 132/33 केवी उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल ने इसे उर्जीकृत किया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है और कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप ट्रांसमिशन कंपनी आदिवासी बाहुल्य इलाकों के विकास के लिये बिजली की ठोस आधारभूत संरचना विकसित कर रही है, ताकि वहां बिजली की सुनिश्चित उपलब्धता से विकास की गतिविधियों को और अधिक गति मिले। साथ ही सिंचाई व घरेलू

उपभोक्ताओं को भरपूर वोल्टेज के साथ निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। लगभग 4.25 करोड़ रूपए की लागत से किए गए इस क्षमता वृद्धि से जिले के ढाई सौ से अधिक गाँवों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इस उपकेंद्र की क्षमता अब 40 एमवीए से बढ़कर 80 एमवीए हो गई है। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री एसके ठाकुर, मुख्यअभियंता सर्व श्री अशोक कुमार वर्मा, केके भौरासे, केएस रामकृष्णा, एसीई अविनाश सोनेकर, एसई पीपी सिंह, मनोज राय, डीएस कतलम, अखिलेश गजपाल, श्रीमती आरएस चंद्राकर, वी मरकाम, राजेंद्र हरमुख, सीआर चंद्रवंशी, नैनेश गोटे, गरिमा नेताम सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

संविदा कर्मियों ने सीएम के नाम लिखा ज्ञापन सौंपा

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के अलग-अलग विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने नियमितिकरण

को लेकर मुख्यमंत्री के नाम छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया ज्ञापन जिले को सयुक्त कलेक्टर श्रीमति सुमन राज को सौंपा है। विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया के समक्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद प्रांत स्तर से नियमितिकरण नहीं, जानकारी नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर काम बंद करने की रणनीति बनाई गई है। जिसके तहत सोमवार को कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है। यदि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे पर गंभीरता नहीं दिखाती तो जल्द ही समस्त संविदा कर्मचारी बढ़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

विधानसभा परिसर से करेंगे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कल विधानसभा परिसर से मुख्यमुंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगें। रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे की मौजूदगी में जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम सरोना में होगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। सरोना में कार्यक्रम स्थल पर 7 एकड़ रकबे में टिशू कल्चर सागौन के 1 हजार 250 पौधे रोपे जाएंगे।

जिले के वन मण्डलाधिकारी श्री व्ही कुमार ने बताया कि राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए ''मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'' शुरू की जा रही है। योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी सहमति पर उनकी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्त संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे भी पात्र होंगे।

श्री कुमार ने बताया कि इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी। इस योजना में मुख्य रूप से 05 वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए कृषकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें टिश्यू कल्चर बांस, क्लोनल नीलगिरी, मिलिया डूबिया, टिश्यू कल्चर सागौन तथा सफेद चंदन शामिल है।

वाप्कोस लिमिटेड किसी अन्य राज्य में ब्लेक लिस्टेड है यह जानकारी नहीं है शासन को : चौबे

■ **बृजमोहन ने उठाया बोधघाट परियोजना पर व्यय की अद्यतन स्थिति का मामला**

रायपुर। बोधघाट परियोजना पर व्यय की अद्यतन स्थिति का मामला भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को विधानसभा में उठाया। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि वाप्कोस लिमिटेड गुरूग्राम किसी अन्य राज्य में ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी शासन को नहीं है।

प्रश्न काल के दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल किया कि क्या बोधघाट परियोजना का काम प्रारंभ होने वाला है? यदि हां तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों? जवाब में कृषि मंत्री ने बता कि वर्तमान में बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना का सर्वेक्षण एवं

अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। अत: निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि अभी बता पाना संभव नहीं है। अग्रवाल ने फिर पूछा कि बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? क्या एजेंसी को पूर्व में भी विभाग ने सर्वेक्षण का कार्य दिया था? यदि हाँ, तो कब? क्या इन्होंने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? यदि हाँ तो कब ? क्या यह एजेंसी किसी राज्य में ब्लेक लिस्टेड है? परियोजना पर अद्यतन कितना व्यय किया जा चुका है? रविंद्र चौबे ने बताया कि बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा भारत शासन के वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम को दिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त एजेंसी को पूर्व में सर्वेक्षण का कार्य नहीं दिया गया है। उक्त एजेंसी के किसी अन्य राज्य में ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी शासन को नहीं है। बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण पर अद्यतन रूपये 1250.87 लाख रूपए बारह करोड़ पचास लाख सतासी हजार) व्यय किया जा चुका है।

श्री अग्रवाल ने फिर सवाल किया कि सर्वेक्षण की पूर्णता तिथि क्या थी? क्या सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगी? जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि बोधघाट बहुउद्देशीय वृहद परियोजना के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य पूर्णता की तिथि 08.02.2022 थी। वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा आंशिक पूर्ण हो चुका है, संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.08.2023 तक अतिरिक्त समयावृद्धि चाही गयी है।

शिक्षित युवाओं के लिए 21 मार्च को प्लेसमेंट कैंप

रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 21 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित है। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से जय अम्बे एमरजेंसी सर्विसेस (आई) प्रायवेट लिमिटेड द्वारा पायलेट एवं ईएमटी के 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 10वीं के साथ हैवी लायसेंस एवं एएनएम, जीएनएम, बी.एस.सी. नर्सिंग, बी.फार्मेसी, डीएमएलटी तथा बी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इन पदों पर चयन होने के उपरांत 11,440 से 12,245 हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित हो सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।

नेशनल अप्रेंटिसशीप अवेयरनेस वर्कशॉप 21 मार्च को

बिलासपुर। क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता रायपुर द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशीप अवेयरनेस वर्कशॉप 21 मार्च को होटल मोटेल बिलासपुर सिटी में किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान अभियंता श्री संजय कुमार पंकज शामिल होंगे।

पीएम आवास योजना पर सदन में हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे. विपक्ष के सवालों का जवाब पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया. पंचायत मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की. इस मामले को लेकर लगातार सदन में हंगामा होता रहा. बाद में भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

प्रश्नकाल के दौरान विधायक पुन्नूलाल मोहले ने राज्य सरकार से पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों की जानकारी मांगी. मोहले ने योजना के तहत बनाए गए मकान के बारे में भी जानकारी मांगी. इसके अलावा उन्होंने इन मकानों के लिए केन्द्र के अंश और राज्य की तरफ से दिए जाने वाले शेयर की भी जानकारी मांगी. जिस पर पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने विस्तार से जानकारी दी. लेकिन जवाब से भाजपा विधायक संतुष्ट नहीं हुए.विधायक पुन्नूलाल मोहले ने एक के बाद एक कई सवाल पीएम आवास योजना को लेकर पूछे. इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ. इस बीच पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे ने स्वीकार किया कि कोरोना के दौरान सरकार राज्यांश नहीं दे पाया था. मंत्री ने कहा कि जो पात्र हितग्राही होंगे, उन्हें आवास दिया जाएगा। नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट- पीएम आवास योजना के सवालों पर मंत्री के जवाब से भाजपा विधायक नाराज रहे. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री पीएम आवास योजना मामले को लेकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं. भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले, शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे. बाद में नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।

विपक्ष का बहिर्गमन

मुर्गा-मुर्गी और अंडे का मामला भी गूंजा

विधानसभा में हंसी-मंजाक और ठिठोली भी देखने को मिली। सदन में मुर्गा-मुर्गी और अंडे का मामला भी गूंजा। विधायक और मंत्री के बीच इस पर जमकर बातें भी हुईं। सदन में खूब ठहाके भी लगे।

दरअसल, विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रदेश के गौठानों में मुर्गी पालन,अंडा उत्पादन की समस्या पर अपनी बातें रखीं। अपने क्षेत्र की समस्या से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर था। इस दौरान गौठानों को देखा। राज्य सरकार के दो अधिकारी भी साथ गए थे। गौठान की महिलाओं ने मुझे बताया कि पहले मुर्गियों को गोदरेज कंपनी का दाना देते थे, तो अंडे का उत्पादन अच्छा था। अब लोकल दाना दे रहे हैं, तो अंडे का उत्पादन घट गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी क्या आप गोदरेज का दाना फिर से दिलवाएंगे?

इस दौरान एक विधायक ने कहा कि पहले अंडा आया या मुर्गी समझ नहीं आ रहा। इस पर मजे लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मेरे कक्ष में आना समझा दूंगा, ये सुनकर सभी हंसने लगे।

धर्मजीत के सवाल पर रविंद्र चौबे मुस्कुराते हुए बोले कि कौन दो आईएएस आपके साथ गए थे पता करता हूं। वो मुर्गियों से बात किए कि नहीं, पहले ज्यादा अंडा देती थी, अब कम दे रही हैं। विभाग में चर्चा करूंगा, पहले कौन सा फीड देते थे?

उन्होंने कहा कि कहीं मुर्गियां ज्यादा उम्र होने की वजह से तो कम अंडा नहीं दे रही हैं। इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि सभी मुर्गियां हैं जवान है, उम्र की बात ही नहीं है। सौरभ सिंह ने कहा कि मुर्गियों से बात करिए कि वो कौन सा दाना खाकर ज्यादा अंडा देंगी। चरणदास महंत ने कहा कि पहले वाला दाना 40 रुपए किलो था, अब 20 रुपए वाला दे रहे हैं इसलिए आधा हो गया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि मुर्गियों से बात करेंगे। इस दौरान धर्मजीत ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार एक अधिकारी पोल्ट्री फॉर्म गए थे। सभी मुर्गियों से कहा कि अंडा दो वर्ना ठीक नहीं होगा। ये देखकर सभी मुर्गियों ने 5-6 अंडे दिए पर एक ने सिर्फ एक ही दिया। अधिकारी ने मुर्गी से पूछा तुमने एक ही अंडे क्यों दिया? इस पर मुर्गी ने कहा कि आपके डर से मैंने एक ही दिया। वैसे मैं मुर्गा हूं। यह सुनकर विधानसभा के सभी सदस्य जमकर ठहाके लगाने लगे।

बृजमोहन ने लगाया 1000 करोड़ के राशन घोटाला का आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सामने आए राशन घोटाले पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वयं राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने जवाब में स्वीकार कर रहे है कि गुड़,चना, शक्कर,चावल राशन दुकानों में सैकड़ों करोड़ का बचत समान था। उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा अतिरिक्त सम्मान सप्लाई कर दी गई। उन्होंने कहा कि मंत्री की यह बात अपने आप में बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती है। साथ ही बृजमोहन ने यह भी बताया कि जब केंद्र सरकार ने आंकड़े भेजें उसके बाद राज्य में जांच की कार्रवाई प्रारंभ की गई पर ऑटोमेटिक पोर्टल बंद कर दिया गया या घोटाले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों के हक में सेंध लगा रही है। यह गरीबों की थाली से खाना चुराने वाली सरकार है। सरकारी भ्रष्टाचार का यह अनूठा नमूना है जो गरीब परिवारों तक को नहीं बख्श रही। उन्होंने कहा की यह 1000 करोड़ का राशन घोटाला प्रमाणित है बावजूद कांग्रेस की यह सरकार विधानसभा की समिति से जांच कि हमारी मांग को ठुकरा रही है।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

पत्रकारों की सुरक्षा

छत्तीसगढ़ में अब पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कानून बनेगा। यह सुखद संकेत है । पिछले दिनों सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए अन्तत: विधेयक पारित कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि राजपाल की अनुशंसा के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा और मीडिया कर्मियों को काम करने में आने वाली दिक्कतों से शायद कुछ मुक्ति मिलेगी । %शायद% इसलिए कह रहा हूं कि कानून तो बहुत सारे बने होते हैं लेकिन उनका अनुपालन ठीक से नहीं होता ।लेकिन पत्रकार सुरक्षा के मामले में ऐसा न हो तो बेहतर। इसमें दो राय नहीं की मीडिया कर्मी खतरों के खिलाड़ी होते हैं ।और खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं होता, जान का नहीं होता, वह मान और अपमान का भी होता है। अखबारों में छपी किसी विशेष खबर का या लेख का संज्ञान लेकर कभी-कभी पत्रकारों पर मुकदमें ठोक दिए जाते हैं। ऐसा हो चुका है। इस मामले पर भी सुरक्षा कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के पहले उस लेख या समाचार का पूरा संज्ञान लिया जाए। उसकी समुचित पड़ताल की जाए कि सही मायने में इससे किसी की मानहानि हुई है अथवा नहीं। कई बार सिर्फ संकेतों के आधार पर यह समझ लिया जाता है कि किसी खास नेता या व्यक्ति की मानहानि कर दी गई है। तब कुछ राजनीतिक अंध भक्त पत्रकार के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट कर देते हैं, और दुर्भाग्यवश उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। शासन को पत्रकार सुरक्षा कानून में इस प्रावधान को शामिल करना चाहिए कि कोई किसी भी मानहानि के मामले में सबसे पहले खबर या लेख का विशेषज्ञों द्वारा न्यायसंगत परीक्षण किया जाए। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संकेतों में, प्रतीकों में लेखक-पत्रकार अपनी बात कहते रहे हैं। अगर वह इतना भी नहीं कर सकेंगे तो अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब नहीं होता। हालाँकि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी भी व्यक्ति की मानहानि कदापि नहीं हो सकती ।अगर मानहानि सत्य पाई गई तो निसंदेह उस लेखक या पत्रकार पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो लकीर का फकीर है ।हालत यह है कि कई बार छपी हुई बातों का अनर्थ लगा लिया जाता है। बहुत पहले दुष्यंत कुमार ने कहा था, मत कहो आकाश में कुहरा घना है /यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो हालत यह है कि अगर पत्रकार कहता है कि आजकल कोहरा घना है, तो हो सकता है सत्ता से जुड़ा कोई व्यक्ति यह समझ ले कि हमारी सरकार की आलोचना की जा रही है। मैंने भी कभी शेर कहा था, हमने अपनी बात कही, वे समझे या निंदा है/ लोकतंत्र शर्मिंदा है। तो सुरक्षा कानून में यह प्रावधान भी बहुत जरूरी है कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के पहले उसकी खबर या लेख पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल जो प्रावधान किए हैं, वे संतोषप्रद हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पत्रकारों को समाचार संग्रह करने के मामले में अब पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। पत्रकार किसी भी शासकीय कार्यालय में जाकर समाचार संग्रह कर सकेंगे और सरकारी विभाग उनके साथ पूरी तरह सहयोग करेगा। अगर किसी पत्रकार को यह महसूस होता है कि उसकी जान का खतरा है, उसे किसी समाचार के मामले को लेकर धमकी दी गई है, तो उसकी सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए । विधेयक पारित कर दिया गया है, यह अभिनंदन योग्य कदम हैम इसमें अगर कुछ कमी रह गई है, तो उसे बाद में दूर भी किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की इस मंशा का स्वागत तो होना ही चाहिए कि वह पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सिंचित है और जो कहा, वह कर दिखाया। मतलब पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पारित तो कर दिया।

आरक्षण मुद्दे पर राजनीकि तेज, कांग्रेस- भाजपा आमने-सामने

भाजपा अपना रुख साफ करें- मरकाम

रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में महिनों से अटका हुआ है। राज्यपाल बदलने के बाद भी अभी तक राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के आदिवासी नेता आरक्षण विधेयक पर अपना रुख साफ करें। आरक्षण संशोधन विधेयक में आदिवासी समाज के लिये 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। बिलासपुर हाई कोर्ट से 58 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत किये जाने पर आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आरक्षण विधेयक राजभवन में रुका है तो इसका खामियाजा आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा हो रहा। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है वह हस्तक्षेप कर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने को कहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पारित करवाये गये आरक्षण संशोधन विधेयक में ओबीसी के लिये भी 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ओबीसी वर्ग से आते है लेकिन ओबीसी वर्ग के हितों के खिलाफ जाकर वे लोग भी आरक्षण विधेयक को राजभवन में रोकवाये है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वर्तमान विधेयक को बनाने के ठोस आधारों का अध्ययन किया है।

कांग्रेस सरकार नौटंकी कर रही है- देवलाल ठाकुर

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार एवं यहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी व उनका मंत्रिमंडल, आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व में जारी 58त्न आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय में फैसले से

पहले 22 बार पेशिया हुई सरकार के पास पर्याप्त अवसर था। सरकार अपना पक्ष रख आदिवासियों का आरक्षण बचा सकती थी पर नही बचा सकी। देवलाल ठाकुर ने कहा फिर सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन लगाई गई जो तथ्यों के अभाव में खारिज हो गई। जब 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रकरण उच्चन्यायालय में सुनवाई चल रहा था तभी सरकार ने बगैर सक्षम प्रक्रिया के तहत 2019 में 82त्न आरक्षण का अध्यादेश लाया, जिसे राज्यपाल से साइन भी करवाया गया था फिर इस अध्यादेश को निश्चित समय में संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कालातीत हो गया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27त्न आरक्षण का प्रावधान किया गया था सरकार के अकर्मण्यता के कारण यह समाप्त हो गया। यह गंभीर टिप्पणियों के साथ न्यायालय में निराकृत हुआ जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण स्थाई रूप से प्रभावित हुआ है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री आवास योजनाः बघेल झूठ परोसकर प्रदेश को गुमराह कर रहे- भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार झूठ परोसकर प्रदेश और आवासहीन हितग्राहियों को गुमराह कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर झूठ का महल खड़ा करने की कला में तो मुख्यमंत्री बघेल को महारत हासिल है! अपने वादों से मुकरने और झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड मुख्यमंत्री बघेल ने बनाया है, भारत की राजनीति में ऐसी कोई और मिसाल शायद ही मिले। प्रदेश महामंत्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बजट भाषण में 2.30 लाख आवास हेतु 32सौ करोड़ रुपए देने की बात कही थी और अब कह रहे हैं कि 7 लाख आवास के लिए 32 सौ करोड़ का बजट रखा गया है। अपनी ही बातों से यू-टर्न लेने में माहिर मुख्यमंत्री बघेल अब यह भी बता दें कि क्या बजट में किए गए प्रावधान में 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश की नहीं है? शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल आवासहीनों का सर्वे प्रदेश में शौक से करवाएं, हम उसका स्वागत करते हैं; लेकिन पहले प्रदेश सरकार केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री आवास, जिसकी सर्वे सूची उपलब्ध है, उन्हें पहले प्रधानमंत्री आवास दें।

बोधघाट परियोजना बस्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी - कांग्रेस

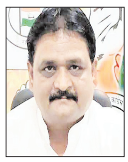

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बोधघाट परियोजना बस्तर के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगी। पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सरकार ने इस परियोजना के लिये कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई थी। कांग्रेस की सरकार ने इसके सर्वे के लिये ठोस प्रयास शुरू किया है। बहुप्रतिक्षित बोधघाट परियोजना पिछले चार दशक से राजनीति की भेंट चढ़ते आ रहा है तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में परियोजना मूर्तरूप नहीं ले पाई थी। बोधघाट के साथ ही परिकल्पित आंध्र की पोलावरम बांध परियोजना 70 फीसदी से अधिक पूरी हो गयी है जबकि छत्तीसगढ़ की यह परियोजना भाजपा शासन में अपने शुरूआती कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस परियोजना के पूरा होने से बस्तर अंचल का सिंचित रकबा 72 फीसदी तक हो जायेगा तथा राज्य के कुल सिंचाई रकबे में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में 264 किमी तक बहने वाली इंद्रवती नदी के पानी का आज छत्तीसगढ़ सिर्फ 11 टीएमसी ही उपयोग कर पाता है लेकिन बोधघाट परियोजना के पूरा होने पर छत्तीसगढ़ इंद्रवती के 300 टीएमसी जल का उपयोग कर पायेगा।

खेलो इण्डिया सेंटर्स की स्वीकृति खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक कदम-साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में 10 नए 'खेलो इण्डिया' सेंटर्स की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की इस बड़ी उपलब्धि के लिए श्री साव ने छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि जब से देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से भारत सरकार हर क्षेत्र में योजना बनाकर काम कर रही है। खेल के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 10 नए 'खेलो इण्डिया' सेंटर्स की स्वीकृति को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को सही दिशा और प्रोत्साहन मिलेगा। श्री साव ने बताया कि फुटबॉल के लिए मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा और बलरामपुर जिले में, तीरंदाजी के लिए दन्तेवाड़ा और महासमुन्द में, हॉकी के लिए बस्तर और जाँजगीर-चाँपा में, कबड्डी के लिए बेमेतरा तथा कुश्ती के लिए धमतरी में खेलो इण्डिया सेंटर्स खोले जाएंगे।

धर्मांतरण को राजनीतिक संरक्षण से बस्तर की स्थिति बिगड़ती जा रही- भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि धर्मांतरण के घातक एजेंडे को प्रदेश सरकार के राजनीतिक संरक्षण के चलते बस्तर क्षेत्र की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जगदलपुर शहर सीमा से लगे तोकापाल के भेजरीपदर के परपा थाना में धर्म विशेष की अनुयायी महिला की मौत के बाद हुए विवाद पर केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर में यह विवाद कोई पहला मामला नहीं है नारायणपुर घटना की पुनरावृत्ति बस्तर में फिर हुई है बाहर से आये हुए ईसाई धर्मावलंबियों ने एक मत होकर पहले स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों पर हमला किया फिर पुलिस पर हमला कर उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। ईसाई मिशनरियों के हमले में एडिशनल एसपी को चोट लगी है, वर्तमान में भी वहां तनाव की स्थिति है और विवाद शांत नहीं हुआ है । पूरा बस्तर आज धर्मांतरण की भठ्ठी में जल रहा है और भूपेश बघेल शासन चैन की बंसी बजा रहा है। कश्यप ने कहा कि धर्मांतरण के कारण सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव को लेकर कुछ समय पूर्व कांग्रेस शासन के इसी कार्यकाल में एसपी ने जो आशंका जताई थी, वह अब सच साबित हो रही है। तब तत्कालीन एसपी सुनील शर्मा ने अपने पत्र में आगाह किया था कि आगे चलकर मूल आदिवासियों और धर्मान्तरित लोगो मे वर्ग संघर्ष के हालात बन सकते हैं।

तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं परिवहनकर्ताओं का भुगतान नहीं, भाजपा का चक्का जाम

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में एन एच 63 पर चक्का जाम करके तेंदूपत्ता संग्राहकों व परिवहनकर्ताओं को उनके लंबित भुगतान की मांग की। इन संग्राहकों व परिवहनकर्ताओं का भुगतान पिछले एक साल से नहीं किया गया है। इस मौके पर श्री गागड़ा ने कहा कि वन अधिकारी व ठेकेदार द्वारा लगातार संग्राहकों व परिवहनकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा था। आज चक्काजाम के दौरान वन अधिकारी ने 10 दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया है। यदि 10 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो भाजपा फिर चक्का जाम करेगी, साथ ही डीएफओ के कार्यालय का घेराव करेगी। श्री गागड़ा ने कहा कि यह सरकार तेंदूपत्ता की दर बढ़ाने का भ्रम फैलाती है जबकि भाजपा शासन में संचालित अन्य सारी योजनाएं बंद हैं। भाजपा शासनकाल में तेंदूपत्ता 7 दिन खरीदा जाता था जबकि इस शासनकाल में एक या दो दिन खरीदी होती है। चरण पादुका व अन्य योजनाएं बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विभिन्न प्रकार से आदिवासीयो को ठगने का कार्य कर रही है जनता शीघ्र उन्हें इसका जवाब देगी।

आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला

रायपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करने के लिये कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन में जाकर महामहिम राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से मिला। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री कवासी लखमा, शिशुपाल सोरी, डॉ. विनय जायसवाल, यू.डी. मिंज, गुलाब कमरो, पुरुषोत्तम कंवर, द्वारकाधीश यादव, रामकुमार यादव, सावित्री मंडावी, लक्ष्मी ध्रुव, चंद्रदेव राय, शशि भगत, प्रीतम राम शामिल थे।

मोदी सरकार ने फिर किसानों से धोखा किया-कांग्रेस

केन्द्र सरकार का मकसद आंदोलन खत्म कराना था उनके वादा को पूरा करना नही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार ने किसान से माफी मांगने के बाद फिर किसानों के साथ धोखा किया है। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कराने तीन काला कृषि कानून लाने के लिए देश भर किसानों से माफी मांगे थे और किसानों की मांगों पर निर्णय लेने के लिए सहमति प्रदान की थी, जो अब तक पूरा नही हुआ और आदत अनुसार मोदी भाजपा सरकार ने किसानों से किये वादे को पूरा नहीं किया जिससे आक्रोशित किसान फिर दिल्ली में आंदोलन पर उतरे हैं। भाजपा का चरित्र है देश की जनता से वादा करना और वादाखिलाफी करना है किसानों के साथ भाजपा ने देश भर के लोगों से जो वादा किया था

उसे भी पूरा नहीं किया है बल्कि भाजपा के नेता ही भाजपा के वादों को चुनावी जुमला करार दिया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देशभर के किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का समर्थन मूल्य देना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। सस्ते दरों पर कीटनाशक, रासायनिक खाद और उपज के लिए मार्केट उपलब्ध कराने का वादा किया था लेकिन तीन काले कृषि कानून लाकर किसानों को अडानी जैसे पूंजीपतियों के गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया जिसका देश भर में विरोध हुआ था। 14 माह के आंदोलन और 700 किसानों की शहादत के बाद मोदी के माफी मांगने से आंदोलन खत्म हुआ था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ धोखा किया है। युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने, सभी के बैंक खाता में 15-15लाख रुपए जमा कराने, 30 रु से 35रु लीटर में पेट्रोल डीजल देने, सस्ते दरों में रसोई गैस उपलब्ध कराने सहित अनेक लोक लुभावने वादे किए थे जो पूरा नहीं हुआ है बल्कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश की जनता गंभीर महंगाई और रोजगार संकट की मार झेल रही है। पेट्रोल-डीजल में मोदी टैक्स लगाकर वसूली की जा रही है, दूध, दही, पुस्तक, कापी, हवाई चप्पल पर जीएसटी लिया जा रहा है, दवाइयों के दाम में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, सरकारी संपत्ति नीलाम हो रही है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और 9 साल में देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है एलआईसी बैक डूब रहे है देश की आर्थिक हालात खराब है आम जनता एवं किसानों को राहत देने में सरकार नाकाम साबित हो गई है।

बुडेनी में त्रिदिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से

रायपुर। प्रशासनिक निष्क्रियता की वजह से अवैध शराब बिक्री के खिलाफ शंखनाद करने वाले थाना क्षेत्र खरोरा के ग्राम बुडेनी में आज सोमवार से सत्ती माता , भैरव बाबा व हनुमान जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारभ हो रहा है । आज देवी पूजन , कल मंगलवार को भव्य कलश यात्रा व परसों बुधवार को मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात रात्रि समय लोक कला मंच द्वारा महतारी का मंचन किया जायेगा। पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

ज्ञातव्य हो कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगा पाने में शासन-प्रशासन की नाकामी से आक्रोशित महिलाओं ने ग्रामीणों के सहयोग से इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है वह कोचियों के घर आने जाने के रास्ते की चौकसी कर पियक्कड़ों को फटकने नहीं दे रहे हैं। साथ ही पियक्कड़ों को इस ओर रुख न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। पहले कुछ दिन लगातार चौकसी के बाद अब वे आकस्मिक रूप से कभी भी किसी भी समय छापामारी अभियान चला रहे हैं जिसकी वजह से पियक्कड़ों की फौज फिलहाल नदारत है और उनका रुख इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नजदीकी ग्राम ?भडहा की ओर हो गया है। बुडेनी के ग्रामीणों का कहना है कि बुडेनी में अवैध शराब बिक्री रुकने से कुछ राहत तो मिली है पर नजदीकी ग्राम ?भडहा में अवैध शराब बिक्री जारी रहने से अब भी अशांति का वातावरण बना हुआ है। बतलाया जाता है कि भडहा में पूर्व में अवैध शराब बिक्री करते पकड़े जा चुके एक व्यक्ति द्वारा अब भी बैखौफ अवैध शराब बेचा जा रहा है जिस पर भडहावासी अब तक रोक लगा पाने में असमर्थ हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.